● वर्ष-6
● अंक-82
रायपुर, रविवार
01 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8>> रिजिजू की कांग्रेस को चुनौती...

तीन दिनों का राज्योत्सव 2026 का शुभारंभ आज

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया होंगे समारोह के मुख्य अतिथि, कल सेंध लेक में सारंग टीम दिखाएगी हवाई करतब

रायपुर। छत्तीसगढ़ की माटी की महक, लोकजीवन के रंग और विकास की उपलब्धियां 'छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026' में एक साथ जीवंत होंगी। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक नवा रायपुर अटल नगर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, मेला ग्राउंड में आयोजित तीन दिवसीय राज्योत्सव प्रदेश की समृद्ध विरासत, जनसामर्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के संकल्प को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस वर्ष राज्योत्सव की थीम "सशक्त नारी, युवा उड़ान" रखी गई है। विभागीय विकास प्रदर्शनियां, लोककला एवं शिल्प, राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियां और भारतीय वायुसेना की सारंग टीम का रोमांचक एयर शो आयोजन के प्रमुख आकर्षण होंगे। राज्योत्सव के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया होंगे। दूसरे दिन 2 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 3 नवंबर को समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भी 2 नवंबर को राज्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। राज्योत्सव उनके ऐतिहासिक योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और राज्य निर्माण से जुड़ी जनआकांक्षाओं को सम्मान देने का अवसर होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ की भूमिका और संभावनाओं को भी आयोजन में रेखांकित किया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने का संदेश राज्योत्सव की थीम को सार्थक बनाएगा।



राज्योत्सव में दिखेगी बदलते बस्तर की तस्वीर

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में इस बार बस्तर की बदलती तस्वीर देखने को मिलेगी। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 'बदलता बस्तरदृसंवरता छत्तीसगढ़' थीम पर अपनी प्रदर्शनी लगाएगा। इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति के साथ बढ़ते पर्यटन और रोजगार के अवसरों से लेकर प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण की पहल को प्रदर्शित किया जाएगा। राज्योत्सव की थीम 'सशक्त नारी, युवा उड़ान' के अनुरूप प्रदर्शनी में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और युवाओं के लिए आजीविका के नए अवसरों पर विशेष जोर रहेगा। प्रदर्शनी में बस्तर के उन क्षेत्रों की झलक दिखाई जाएगी, जहां कभी नक्सलवाद के कारण पर्यटन गतिविधियां सीमित थीं और अब स्थानीय समुदाय पर्यटन से जुड़कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कांगेर घाटी की जंगल सफारी और गुफाओं के साथ स्टार गेजिंग के लिए प्रसिद्ध कोण्डागांव की पुष्पाल घाटी, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के मट्टीमरका और सुकमा के तुंगल डैम को मॉडल के जरिए दिखाया जाएगा। धुड़मारास के धुरवा होमस्टे और देवगुड़ियों के संरक्षण के माध्यम से बस्तर की संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी आजीविका को भी प्रदर्शित किया

कार्यक्रमों, शिल्पग्राम और अन्य गतिविधियों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और विकास यात्रा को प्रस्तुत किया जाएगा।

विभागीय प्रदर्शनियों में शासन की प्रमुख योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास कार्यों की उपलब्धियों की झलक मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मानव पूंजी विकास, विकसित भारत और अंजोर छत्तीसगढ़ मिशन जैसे विषयों पर केंद्रित प्रदर्शनियां प्रदेश की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं से परिचित कराएंगी। शिल्पग्राम में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, शिल्प और कारीगरों के हुनर के विविध रूप देखने को मिलेंगे। राज्योत्सव के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा 40 राज्य स्तरीय अलंकरण एवं पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।

राज्योत्सव का विशेष आकर्षण 2 नवंबर को सुबह 11 बजे से नवा रायपुर के सेंध लेक क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का एयर शो होगा। पांच स्वदेशी 'ध्रुव' हेलीकॉप्टरों के साथ टीम के पायलट सामूहिक उड़ान भरकर आकर्षक हवाई संरचनाओं और साहसिक करतबों का प्रदर्शन करेंगे। मोर से प्रेरित रंग-सज्जा वाले हेलीकॉप्टरों की उड़ान और उनका सटीक तालमेल दर्शकों को रोमांचित करेगा। गुप कैप्टन अभिजीत कुमार के नेतृत्व वाली सारंग टीम में महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर सुश्री अंकिता और स्क्वाड्रन लीडर सुश्री अक्षया भी शामिल हैं। यह प्रदर्शन भारतीय वायुसेना के शौर्य, अनुशासन और उड़ान दक्षता के साथ स्वदेशी विमानन तकनीक की क्षमता का परिचय देगा।

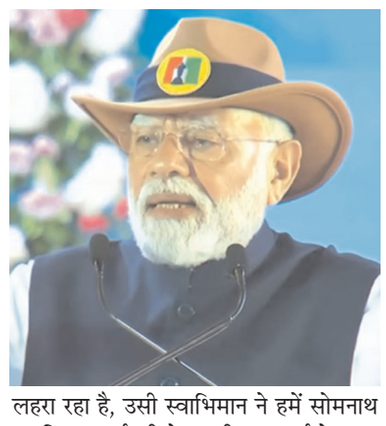
एकता दिवस परेड में शामिल हुए प्रधानमंत्री

सरदार पटेल के फैसलों ने देश को एकजुट किया : प्रधानमंत्री

अहमदाबाद । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता नगर के परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें देश की एकता, विविधता और सामूहिक शक्ति की झलक देखने को मिली। परेड में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव को प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता को आकार देने और उसकी रक्षा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश में नक्सलवाद को एक निर्णायक झटका दिया गया है।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमें जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है और एकता हमें एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसलिए हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और एकता दिवस, ये तीनों अब पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय एकता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सरदार वल्लभभाई पटेल के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने केवल देश के भूगोल को ही नहीं जोड़ा, बल्कि पूरे राष्ट्र को भावनात्मक एकता के सूत्र में भी बांधा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के माध्यम से उन्होंने देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत भी की थी। इस महान कार्य के 75 वर्ष इस वर्ष पूरे हो रहे हैं। जिस तरह सोमनाथ मंदिर का ध्वज हजार वर्षों से तमाम आक्रांताओं की मंशा को नाकाम करते हुए पूरे स्वाभिमान के साथ



लहरा रहा है, उसी स्वाभिमान ने हमें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की प्रेरणा दी। इस वर्ष देश इस पर्व को भी पूरे उत्साह के साथ मना रहा है।

प्रधानमंत्री एकता नगर के पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 426.71 करोड़ रुपये की 31 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देना और पर्यटन के नए आकर्षण विकसित करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता नगर में कुल 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 307.83 करोड़ रुपये की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 118.88 करोड़ रुपये की करीब आठ परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इन विकास कार्यों में नए होटल, क्रूज, रेन फॉरेस्ट, इको ट्रेल, सड़क, पुल, पानी और सफाई व्यवस्था से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के शुरू होने से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने आने वाले पर्यटकों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी।

रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली आज

दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित एक बड़ी रैली को देखते हुए मध्य दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रह सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक यातायात को नियंत्रित किया जा सकता है और आवश्यकतानुसार रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले यात्रियों से विशेष अनुरोध किया गया है कि वे असुविधा से बचने के लिए



सड़क के किनारे वाहन पार्क करने से बचें ताकि ट्रैफिक का सुचारू संचालन बना रहे और किसी भी आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस व अन्य आपात वाहनों के लिए रास्ते पूरी तरह खुले रहें। यात्री किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने और रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट प्राप्त करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल व हेल्पलाइन माध्यमों से जुड़े रह सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित होने वाले मार्गों से बचें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर घर से निकलें। भीड़भाड़ से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का अधिक से अधिक उपयोग करें।

देश में पहली वोट चोरी नेहरू के समय हुई थी : संबित

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने विपक्षी इंडिया गठबंधन द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किए गए सांकेतिक सार्वजनिक महाभियोग पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्र भारत में वोट चोरी की पहली घटना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ताकि सरदार वल्लभभाई पटेल को प्रधानमंत्री का पद न मिल सके। चुनावी गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए, पात्रा ने भारत के पहले गृह मंत्री की जयंती के अवसर पर कहा कि यह ऐतिहासिक वोट चोरी एक निर्विवाद तथ्य है, जिसे गांधी परिवार के पहले सदस्य ने अंजाम दिया था। राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पात्रा ने कहा आज, वोट चोरी के आरोपों के संदर्भ में जिस मुद्दे पर खड़गे जी बात कर रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ- हाँ, वोट चोरी का दावा सच है। वास्तव में वोट चोरी हुई थी। आज 31 अक्टूबर है, जो आदरणीय सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती है। और अगर भारत में कभी कोई वोट चोरी हुई है, तो वह गांधी परिवार के पहले सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिन्होंने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के वोट चुरा लिए थे।

राज्यपाल डेका ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें किया नमन



रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने लौह पुरूष, राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार, भारत रत्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती पर आज लोकभवन में उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल श्री डेका ने अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए नमन किया।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

सोना 3200 रूपए टूटकर 10 महीने के निचले स्तर

नई दिल्ली। बहुमूल्य धातुओं के वैश्विक बाजारों में आई तेज बिकवाली के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना ?3,200



की भारी गिरावट के साथ 10 महीने के निचले स्तर 1,42,000 प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया, जो शुक्रवार को 1,45,200 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इससे पहले सोने का यह निचला स्तर 26 दिसंबर 2025 को 1,42,300 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया था। सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी जोरदार गिरावट आई और यह 4,200 टूटकर 1,86,000 प्रति किलोग्राम पर आ गई। वैश्विक स्तर पर यूएस फेडरल रिजर्व के सख्त रुख की संभावनाओं और ऊर्जा कीमतों में तेजी के कारण सर्राफा बाजार पर गहरा दबाव बना हुआ है। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के हाजिर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में बिकवाली का दबाव बना रहा।

राहुल भारत में बांग्लादेश जैसा सत्ता परिवर्तन चाह रहे : जोशी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह भारत में बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप



लगाया कि राहुल गांधी देश के आंतरिक लोकतांत्रिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। जयपुर में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोशी ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात चाहती है, जहां सत्ता परिवर्तन के दौरान हिंसा हुई और हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं सामने आईं। उन्होंने कहा कि भारत में सरकार बदलने का एकमात्र संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीका चुनाव है। जनता अपने वोट के जरिए सरकार चुनती है और उसे बदल भी सकती है। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी और उनके आसपास के कुछ लोग खुले तौर पर सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं और वहां के युवाओं से प्रेरणा लेने की बात कहते हैं।

राहुल गांधी को हमेशा मॉक प्रधानमंत्री ही बनाए रखिए

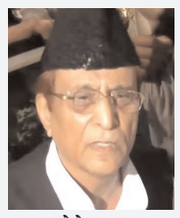
नई दिल्ली। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मॉक जन महाभियोग कार्यक्रम आयोजित करने के बाद भाजपा ने विपक्ष पर



पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष चाहे कितनी भी मॉक संसद चलाए या रैलियां निकाले, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की उसकी कोशिश सफल नहीं होगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष राहुल गांधी को जिंदगीभर अपना मॉक प्रधानमंत्री बनाए रख सकता है। पात्रा ने कहा कि दुनिया समझ चुकी है कि राहुल गांधी में आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है और यह सैटेलाइट कभी लॉन्च नहीं होने वाला। उन्होंने विपक्ष के कार्यक्रम को संसद और लोकतंत्र का मजाक बताया। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि केवल घुसपैठिए ही जानबूझकर फॉर्म-6 नहीं भर रहे हैं और न ही नोटिस का जवाब दे रहे हैं।

जेल से निकलते ही आजम खान को ईडी ने किया गिरफ्तार

लखनऊ। सपा नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ 11 महीने बाद रामपुर जेल से बाहर आए। लेकिन, जेल के गेट पर ही प्रवर्तन निदेशालय ने आजम को हिरासत में ले लिया। जैसे ही वे बाहर



निकले, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आजम से पूछताछ की और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। इस दौरान श्वष्ठ के अधिकारियों और आजम के बीच तीखी बहस भी हुई। इस बीच, भावुक होते हुए आज़म ने कहा किअब कहने के लिए बचा ही क्या है? मुसलमान होने की यही कीमत चुकानी पड़ती है। एक मुसलमान ने यूनिवर्सिटी बनाई। बस यही गलती है। यही हमारा एकमात्र अपराध है। इस बीच, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम घर के लिए निकल गए। दरअसल, आजम की रिहाई से लगभग 15 मिनट पहले प्रवर्तन निदेशालय (श्वष्ठ) की एक टीम जेल पहुंच गई थी। इसके अलावा, वहां ष्टत्रक्षत्र के 24 जवानों को भी तैनात किया गया था। 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो पैन कार्ड से जुड़े एक मामले में आजम और अब्दुल्ला को सुनाई गई 10 साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी थी।

ज्ञानेश कुमार ने आपराधिक कृत्य किया, बोले मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीधे निर्देशोंपर चुनाव आयोग



चला रहे हैं। शनिवार को नई दिल्ली के राजाजी मार्ग स्थित मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन द्वारा एक सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के इस प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम में खड़गे ने कहा, सीईसी ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सीधे निर्देशों पर आयोग चला रहे हैं। सात महीने पहले, विपक्ष के 193 सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में सीईसी को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन, हमारे नोटिस खारिज कर दिए गए और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए, आज हम जो प्रस्ताव लाए हैं, उसका उद्देश्य एक संवैधानिक संस्था की गरिमा की रक्षा करना है। सीईसी के प्रति हमारी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कुर्सी खतरे में आई

नेशनल कॉन्फ्रेंस के 41 में से 24 विधायकों ने कर दी बगावत!

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की सियासत में इन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर जो कुछ घट रहा है, वह महज मंत्रिमंडल विस्तार से उपजी नाराजगी नहीं है। इसके पीछे सत्ता की हिस्सेदारी, पार्टी में लोकतंत्र, अब्दुल्ला परिवार का नेतृत्व और चुनावी वादों को पूरा करने की जवाबदेही जैसे कई सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए मुश्किल यह है कि विपक्ष से ज्यादा चुनौती अब उनकी अपनी पार्टी के भीतर से उठती दिखाई दे रही है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को एकजुट रखकर उन्होंने सत्ता हासिल की थी, उसी पार्टी के भीतर अब असंतोष खुलकर सामने आने लगा है।

मंगलवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शुक्रवार की शाम श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की एक अहम बैठक हुई। यह बैठक लोलाब के विधायक कैसर जमशेद लोन के आवास पर आयोजित की गई। बताया जा रहा है कि कम से कम 18 विधायक बैठक में शामिल हुए, जबकि छह अन्य विधायकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस तरह असंतुष्ट खेमे में 24 विधायकों के होने की चर्चा ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।

इन विधायकों की नाराजगी केवल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने तक सीमित नहीं बताई जा रही। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाया जाए, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी सहित कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए और पूरे मंत्रिमंडल का नए सिरे से पुनर्गठन हो। इसके साथ ही पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र, विधायकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और चुनावी घोषणापत्र को लागू करने के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करने की मांग भी उठाई गई है।

असंतुष्ट विधायकों का आरोप है कि पार्टी और सरकार कुछ चुनिंदा लोगों के इर्द-गिर्द सिमटती जा रही है। विधायकों को जनता के बीच जाना पड़ता है, लेकिन



सरकार के फैसलों में उनकी आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा। बैठक में कुछ वरिष्ठ नेताओं के भावुक होने और पार्टी नेतृत्व तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार के व्यवहार को लेकर शिकायतें सामने आने की खबरें भी हैं। यह घटनाक्रम बताता है कि नाराजगी की जड़ें काफी गहरी हैं।

दरअसल, उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार ही पार्टी के भीतर नई राजनीतिक लड़ाई का कारण बन गया। मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अली मोहम्मद सागर, शमीमा फिरदौस, मीर सैफुल्लाह और अल्ताफ अहमद कालू को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके साथ मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या नौ हो गई, जो 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा है। लेकिन इस विस्तार ने सभी को संतुष्ट करने के बजाय कई वरिष्ठ विधायकों को नाराज कर दिया। अब्दुल मजीद लरमी की सार्वजनिक नाराजगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनी। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर वह भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वह कैबिनेट में शामिल होने के योग्य थे। उन्होंने यहां तक सवाल उठाया कि जिस विधायक को मंत्री बनाया गया है, वह मैट्रिक भी पास नहीं है, जबकि वह स्वयं कानून के स्नातक हैं।

दूसरी तरफ मुबारक गुल के समर्थकों ने पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शन किया। गुल को महासचिव बनाए जाने के बाद संगठनात्मक स्तर पर हुए फैसलों ने भी विवाद को हवा दी। अब उन्हें महासचिव पद से हटाए जाने और सलमान अली सागर को इस पद पर बनाए रखने के घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर असमंजस और बढ़ा दिया है। मुबारक गुल ने 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के अंदरूनी घटनाक्रम पर खुलासा करने का ऐलान किया है। उनका यह बयान आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसके अलावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का पार्टी छोड़ने का ऐलान है। उन्होंने 3 नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोकसभा सदस्यता दोनों से इस्तीफा देने की घोषणा की है। रुहुल्लाह ने अपने तीखे बयान में अब्दुल्ला परिवार के नेतृत्व पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी और जम्मू-कश्मीर को एक राजनीतिक विरासत की तरह चलाया जा रहा है।

कटघोरा नपा अध्यक्ष के आवास पर ईओडब्ल्यू की दबिश, नगर सेना रिमाण्ड पर



कोरबा। छत्तीसगढ़ में चर्चित डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) मामलों की जांच के बीच ईओडब्ल्यू की टीम के कटघोरा पहुंचने की जानकारी मिली है। नगर पालिका अध्यक्ष राज जायसवाल के वार्ड क्रमांक 8 स्थित मोहलाइन भांठा निवास पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की टीम के पहुंचने की जानकारी सामने आई है। टीम ने करीब एक घंटे तक मौके पर रहकर दस्तावेजों की पड़ताल की। एक अन्य ठिकाने पर भी जांच टीम के पहुंचने की सूचना है। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू की टीम शुक्रवार को राज जायसवाल के आवास पर पहुंची और वहां उपलब्ध दस्तावेजों एवं अन्य रिकॉर्ड की जांच की। कार्रवाई के दौरान टीम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जांच पूरी करने के बाद टीम के वापस लौटने की बात कही जा रही है।

ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई का सटीक कारण क्या है, जांच का दायरा कितना व्यापक है। इसका डीएमएफ से जुड़े मामलों से कोई संबंध है या नहीं, इसे लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि यह जांच डीएमएफ के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से आधिकारिक बयान सामने आने तक का इंतज़ार करना होगा।तथ्यों और दस्तावेजों की पड़ताल से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। पालिका अध्यक्ष के अलावा नगर सैनिक दिलीप केंवट को रिमांड पर लेने की भी चर्चा है। बताया जाता है कि यह नगर सैनिक पूर्व में कटघोरा एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रहा है, जो दो से तीन एसडीएम की सुरक्षा में तैनात रहा है। आशंका जताई है कि कोयला खदान विस्तार के दौरान जमीन और मुआवजा से जुड़े पुराने मामलों के साथ अन्य प्रशासनिक प्रकरणों के दस्तावेजों की जानकारी जुटा रही है।

नक्सल डंप से 143 बीजीएल राउंड जब्त बरामद



बीजापुर। थाना उसूर क्षेत्र अंर्तगत पुजारी कांकेर कैंप से लगभग 05 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में पहाड़ी भूभाग में पामेड़ एरिया कमेटी के अज्ञात नक्सलियों द्वारा संदिग्ध नक्सली डंप की सूचना पर के. कबीब (आईपीएस), आईजी सेक्टर छत्तीसगढ़ के दिशा-निर्देशानुसार तथा बीएस. नेगी, डीआईजी ऑप्स रेंज बीजापुर के मार्गदर्शन में 196वीं वाहिनी सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुजारी कांकेर के पास जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान आज शनिवार को बड़े नक्सल डंप से 143 बीजीएल राउंड बरामद किया गया है। बीजापुर एसपी उमेश कुमार गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। थाना उसूर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 196वीं वाहिनी सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम बीजापुर के थाना उसूर क्षेत्र के पुजारी कांकेर गांव के पास जंगलों में सर्चिंग के दौरान अत्यंत सतर्कता के साथ चलाए गए इस सघन सर्चिंग अभियान के दौरान पामेड़ एरिया कमेटी के अज्ञात नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 143 बीजीएल राउंड एवं एक सिंटेक्स बरामद किया है। बरामद नक्सली डंप की समस्त सामग्री को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना उसूर को सुपुर्द कर दिया गया है।

गुणवत्ताहीन चेकडैम निर्माण पर बलरामपुर कलेक्टर का एक्शन, 9 लाख से ज्यादा वसूली के निर्देश



बलरामपुर। जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। चेकडैम निर्माण में अनियमितता सामने आने पर कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें एक तकनीकी सहायक की संविदा सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही 9।13 लाख रुपए की वसूली और संबंधित 17 कार्यों का भुगतान रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल बलरामपुर जिले में चेकडैम निर्माण में गुणवत्ता हीन कार्य किए जाने को लेकर शिकायत मिली थी। इसके बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य कार्यालय के निर्देश पर मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) से 17 चेकडैम कार्यों की जांच कराई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार कुछ कार्यों में कंक्रीट की गुणवत्ता और उप-संरचनाओं के निर्माण में तकनीकी कमियां मिलीं। प्रतिवेदन में कंक्रीट की सतह पर प्लास्टर किए जाने का भी जिक्र है। ांच में कार्यों का अधिक मूल्यांकन पाया गया इस पर तकनीकी सहायक रोहित कुमार, अविनाश भारती एवं कृपाशंकर गुप्ता से 9।13 लाख रुपए की वसूली के निर्देश जारी किए गए हैं। अनियमितता के आधार पर जनपद पंचायत राजपुर में पदस्थ तकनीकी सहायक रोहित कुमार की संविदा सेवा 30 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर समाप्त कर दी गई।

जांच के दायरे में आए सभी 17 चेकडैम कार्यों का भुगतान रोक दिया गया है। इनमें 12 कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बलरामपुर और 5 कार्य जनपद पंचायत राजपुर के हैं।

तकनीकी सहायक अविनाश भारती और कृपाशंकर गुप्ता पर महात्मा गांधी नरेगा/अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। साथ ही दोनों को अंतिम चेतावनी पत्र भी जारी किया गया है। लेक्टर ने पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी तय करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किए हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बलरामपुर के कार्यपालन अभियंता सच्चिदानंद कांत और उप संभाग राजपुर के अनुविभागीय अधिकारी जानूराम सोनवानी से जवाब मांगा गया है। जनपद पंचायत राजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय दुबे और कार्यक्रम अधिकारी मानसाय सिदार से भी जवाब तलब किया गया है।

बागबहरा में तेंदुए का खौफ, घर में घुसकर बकरी का शिकार

- वन विभाग ने कराई मुनादी



महासमुंद। बागबाहरा वन परिक्षेत्र पंडरीपानी गांव के आसपास तेंदुए की मौजूदगी ने ग्रामीणों की दहशत बढ़ा दी है। पंडरीपानी गांव में शुक्रवार रात तेंदुआ ग्रामीण के घर में घुसकर दलान में बंधी बकरी का शिकार कर लिया। इस घटना में बकरी की मौत हो गई।सुबह जब ग्रामीण जगा तो उसने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। बताया जा रहा है कि ये घटना बिसाहू चक्रधारी के घर पर हुई है। वहीं घटना के बाद से परिवार और आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है।

बागबाहरा क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियों का मामला नया नहीं है। इससे पहले 3 अक्टूबर को पंडरीपानी के समीप करिपाट पहाड़ क्षेत्र में लकड़ी लेने गए एक युवक लक्ष्मीनारायण यादव पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। इसके अगले ही दिन ग्राम झिटकी में तेंदुआ एक घर के भीतर घुस गया और एक ही परिवार के छह सदस्यों को घायल कर दिया था। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने विशेष रेस्क्यू अभियान चलाकर तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा था। हालांकि, बाद में उस तेंदुए की मौत होने की जानकारी सामने आई थी। बेहराभांठा, बनियातोरा और परकोम तक तेंदुए की मौजूदगी की चर्चाइसके अलावा बोकरामुड़ा, बोकरामुड़ा खुर्द, बेहराभांठा, बनियातोरा और परकोम सहित आसपास के गांवों में भी अलग-अलग समय पर तेंदुए की मौजूदगी की सूचनाएं सामने आई है।

20 अक्टूबर की दरम्यानी रात भी कुछ गांवों में तेंदुए की गतिविधियां देखे जाने की जानकारी मिली थी। लगातार अलग-अलग स्थानों से मिल रही सूचनाओं ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने प्रभावित गांवों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की है।

मुगेली नाबालिग मर्डर केसः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पलटा सीजेएम का फैसला

- दोनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल



मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में नाबालिग के मर्डर केस में आखिरकार दोनों आरोपियों के जेल दाखिल कर दिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ष्ठछ्रू) न्यायालय ने आरोपियों का न्यायिक रिमांड खारिज कर दिया था। राज्य शासन ने ष्ठछ्रू के आदेश को अपर सत्र न्यायालय में चुनौती दी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए 29 अक्टूबर को पूर्व आदेश निरस्त कर दिया। जिसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना 20 अक्टूबर 2026 को पुलिस को मिली थी। सिटी कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और गवाहों के कथनों के आधार पर अपराध क्रमांक 343/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान अजीत घृतलहरे और साहिल खाण्डे को गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड की मांग की गई, लेकिन ष्ठछ्रू न्यायालय ने रिमांड आवेदन स्वीकार नहीं किया। न्यायालयीन आदेश में गिरफ्तारी से संबंधित प्रक्रिया और दस्तावेजों में कमियों का उल्लेख किया गया था। उपलब्ध आदेश के अंश के अनुसार, कथन दर्ज किए जाने के समय का उल्लेख नहीं होने सहित प्रक्रियागत बिंदुओं पर सवाल उठे। न्यायालय ने विवेचना अधिकारी प्रशिक्षु उपनिरीक्षक नवीन कुमार से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश भी दिया। दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़े जाने का आदेश हुआ। इस घटनाक्रम के बाद पीड़ित परिवार की चिंता बढ़ गई। परिवार ने आरोपियों की रिहाई के बाद धमकी मिलने की शिकायत भी पुलिस से की थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यायिक रिमांड आवेदन खारिज होना हत्या के मामले में दोषमुक्ति का निर्णय नहीं था। मामला विवेचना और न्यायालयीन प्रक्रिया के अधीन बना हुआ था। 23 अक्टूबर को मृतिका के दादा उत्तम मोहले, परिजनों, ग्रामीणों और सरपंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। परिवार ने आर्थिक सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। ज्ञापन में परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति और घटना के बाद पैदा हुए भय के माहौल का उल्लेख किया गया था।परिजनों का कहना था कि एक ओर उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी को खो दिया है, वहीं दूसरी ओर न्यायिक रिमांड खारिज होने के बाद परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। परिवार की मांग थी कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, आरोपियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए और परिवार को आर्थिक सहायता के साथ सुरक्षा भी मिले। परिजनों ने धमकी मिलने की शिकायत सिटी कोतवाली में देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी। 26 अक्टूबर को कलेक्टर अमृत विकास तोपनो और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल पीड़ित परिवार से मिलने नेवासपुर स्थित उनके घर पहुंचे।

हल्बा चौकी से हटाए गए महिला इंस्पेक्टर और एएसआई

- अवैध वसूली के आरोपों पर कांकेर पुलिस विभाग का एक्शन. एसआई पीयूष यादव को मिली नई जिम्मेदारी.

कांकेर। चारामा ब्लॉक के हल्बा क्षेत्र के करीब 20 गांवों के जनप्रतिनिधियों ने पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली के आरोप लगाए। ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। जिसके बाद कांकेर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है। एसपी निखिल राखेचा ने हल्बा चौकी प्रभारी दीपा केंवट और सहायक उप निरीक्षक चेतन साहू को चौकी से हटाकर लाइन अटैच कर दिया है। प्रशिक्षु उप निरीक्षक पीयूष यादव को हल्बा चौकी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। हल्बा क्षेत्र के करीब 20 गांवों के जनप्रतिनिधियों ने महिला चौकी प्रभारी और एएसआई पर अवैध वसूली, पैसे मांगने और पैसे नहीं देने पर ट्रैक्टर जब्त करने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी निखिल राखेचा से मुलाकात की थी और लिखित शिकायत सौंपते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को हटाने तथा निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

जनप्रतिनिधियों का आरोप था कि महानदी किनारे बसे गांवों में ग्रामीण ग्राम पंचायत की अनुमति से घरेलू उपयोग के लिए ट्रैक्टर के माध्यम से रेत का परिवहन करते हैं। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर पैसों की मांग की जाती थी और मांग पूरी नहीं होने पर कार्रवाई की धमकी दी जाती थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने आदेश जारी करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को हल्बा चौकी से हटाकर लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही प्रशिक्षु उप निरीक्षक पीयूष यादव को चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल, पुलिस विभाग की इस कार्रवाई को जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कोर्ट ने प्रिंसिपल को सुनाई 6 साल सश्रम कारावास की सजा

बलौदाबाजार। स्कूल में पढ़ने वाली 9 नाबालिग छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने शिक्षक को दोषी ठहराते हुए 6 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पलारी थाना क्षेत्र के टीपावन स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) गिर्जेश प्रताप सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा ने पैरवी की। मामले में सामने आया कि आरोपी शिक्षक ने एक छात्रा को उसके पिता का हालचाल पूछने के बहाने अपने स्टाफ रूम में बुलाया था। बातचीत के दौरान उसने छात्रा की पीठ और कमर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। इसके बाद उसके सीने को छूने की कोशिश की। शिक्षक की इस हरकत से छात्रा डर गई और वहां से भाग निकली। घटना के बाद स्कूल की एक शिक्षिका ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया। इसी दौरान उन्होंने छात्राओं से पूछा कि क्या किसी के साथ इस तरह की कोई घटना हुई है।

एसआई पर पैसे मांगने व ट्रैक्टर जब्ती की धमकी का आरोप

कांकेर। नक्सलवाद के साये से बाहर निकलकर शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे कांकेर जिले में अब पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चारामा ब्लॉक के हल्बा क्षेत्र के करीब 20 गांवों के जनप्रतिनिधियों ने महिला चौकी प्रभारी और एक एसआई पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। जनप्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को पद से हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि महानदी के किनारे बसे हल्बा क्षेत्र के ग्रामीण घरेलू उपयोग के लिए ग्राम पंचायत की अनुमति से ट्रैक्टर के माध्यम से रेत का उत्खनन और परिवहन करते हैं। लेकिन इस दौरान महिला चौकी प्रभारी और एक एसआई द्वारा कथित तौर पर पैसों की मांग की जाती है। आरोप है कि पैसे नहीं देने पर ट्रैक्टर जब्त करने और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती है।

बस्तर में खौफ का दौर खत्म! 116 नेताओं की सुरक्षा में होगी कटौती

जगदलपुर। एक दौर था जब बस्तर में नेताओं का काफिला निकलता था तो साथ में सुरक्षाकर्मियों की लंबी कतार भी चलती थी। वजह थी नक्सलियों का वो खौफ, जिसने बस्तर की राजनीति को कई गहरे जख्म दिए। इसी नक्सली हिंसा में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा की झीरम घाटी में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद कर्मा परिवार को सुरक्षा दी गई। भीमा मंडावी जैसे जनप्रतिनिधि भी नक्सली हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद सरकार ने नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा घटाने का फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश के 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया है। इनमें से और से श्रेणी में सुरक्षा घटाई गई है। बीजेपी और कांग्रेस के 9 नेताओं की सुरक्षा को घटाकर कर दिया गया है। इसके अलावा वन मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की सुरक्षा में भी कटौती की गई है।

केरिपुबल ने मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस

बीजापुर। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को 170वीं वाहिनी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बीजापुर में राष्ट्रीय एकता दिवस देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। संपूर्ण कार्यक्रम बी.एस. नेगी, उपमहानिरीक्षक, रेंज बीजापुर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। 170वीं वाहिनी मुख्यालय परिसर में उपस्थित अधिकारियों एवं जवानों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। साथ ही देशवासियों के बीच एकता और राष्ट्रीय एकजुटता की भावना को मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 08 बजे रन फॉर यूनिटी (एकता दौड़) के साथ हुआ। यह दौड़ 229वीं वाहिनी मुख्यालय, बीजापुर से प्रारंभ होकर 170वीं वाहिनी मुख्यालय, बीजापुर तक आयोजित की गई। इसमें बीजापुर रेंज की 22, 85, 153, 168, 170, 196, 214, 222 एवं 229वीं वाहिनी के अधिकारियों और जवानों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर एनसीसी कैडेटों ने ली एकता की शपथ

जगदलपुर। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 जगदलपुर में 1 सीजी गर्ल्स बटालियन एनसीसी परचनपाल के तत्वावधान में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में गरिमामय माहौल में मनाई गई। यह आयोजन कमान अधिकारी कर्नल सुशील कुमार राणा के मार्गदर्शन एवं आदेशानुसार संपन्न हुआ। पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन एनसीसी अधिकारी कैप्टन हेमपुष्पा लता ध्रुव द्वारा किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण रखने के संकल्प के साथ शपथ ग्रहण समारोह से हुआ, जिसमें सभी कैडेटों और विद्यालय परिवार ने देश सेवा की शपथ ली। बौद्धिक सत्र के दौरान संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता शिव प्रताप चौहान ने सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रेरक जीवन परिचय, उनके संघर्षों और 500 से अधिक रियासतों का विलय कर अखंड भारत के निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके पश्चात विद्यालय के प्राचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित किया।

4 फीसदी मासिक मुनाफे का लालच, 3.12 करोड़ की चपत

- इंदौर से पकड़ा गया शेयर ट्रेडिंग ठगी का मुख्य आरोपी



धमतरी। शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा कमाने की चाहत कई निवेशकों को भारी पड़ गई। हर महीने 4 फीसदी मुनाफा देने का वादा, स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इकरारनामा और सुरक्षा के नाम पर बैंक चेक। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए तमाम तरीके अपनाए गए, लेकिन जब रकम वापस करने की बारी आई तो कथित निवेश कारोबारी गायब हो गया। धमतरी में 3 करोड़ 12 लाख रुपये से अधिक की कथित वित्तीय धोखाधड़ी के इस मामले में पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी विक्रम सिंह शाह को मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी धमतरी के कलेक्ट्रेट रोड स्थित अपने 'वेल्थ ट्रैकर' कार्यालय के जरिए लोगों को शेयर मार्केट और ट्रेडिंग ऐप में निवेश करने के लिए प्रेरित करता था। निवेश की गई रकम पर हर महीने 4 प्रतिशत ब्याज या मुनाफा देने का भरोसा दिलाया जाता था। शुरुआत में कुछ निवेशकों को लाभ की राशि देकर उनका विश्वास जीता गया, लेकिन बाद में मूलधन और मुनाफे का भुगतान बंद कर दिया गया। इस मामले की शिकायत बालोद जिले के गुरूर निवासी 62 वर्षीय शिवकुमार साहू ने की थी। शिकायत के अनुसार, उन्होंने अपने परिजनों के साथ आरोपी के पास 25 लाख रुपये निवेश किए थे। शुरुआत में रकम पर लाभ मिलने की उम्मीद बनी रही, लेकिन बाद में भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। घटनास्थल धमतरी के सिटी कोतवाली क्षेत्र में होने के कारण प्रकरण की विवेचना धमतरी पुलिस को सौंपी गई। पुलिस ने आरोपी विक्रम सिंह शाह के खिलाफ धारा 420 भादंवि में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो ठगी की रकम और पीड़ितों की संख्या का दायरा बढ़ता गया। पुलिस के अनुसार, अब तक की जांच में 3 करोड़ 12 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी सामने आई है। इस मामले में कई निवेशकों की बड़ी रकम फंसने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, संगीता सिन्हा से 81 लाख रुपये, अंबिका प्रसाद सोनवानी से 60 लाख रुपये, भूषण सिन्हा से 28 लाख रुपये, चेतन सिन्हा से 16 लाख रुपये और प्रभुलाल सिन्हा से 12 लाख रुपये लेने की जानकारी जांच में सामने आई है। इनके अलावा अन्य निवेशकों की रकम भी इस मामले में शामिल है। मासिक मुनाफे के आकर्षक वादे के साथ निवेशकों को इकरारनामा और चेक दिए जाते थे, ताकि उन्हें रकम सुरक्षित होने का भरोसा रहे। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि निवेशकों से जुटाई गई करोड़ों रुपये की राशि आखिर कहां गई और किन खातों या माध्यमों से उसका लेन-देन किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की तलाश तेज की।

आपराधिक मामले में फंसे शिक्षक निलंबित



गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। जिले के मरवाही विकासखंड के एक शासकीय शिक्षक पर आपराधिक मामले में शिकंजा कसा गया है। थाना मरवाही में दर्ज आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में निरुद्ध रहने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने माध्यमिक शाला लिटियासरई में पदस्थ शिक्षक एलबी लालबहादुर प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, शिक्षक लालबहादुर प्रजापति के विरुद्ध मरवाही थाने में गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 26 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला जेल गौरेला भेज दिया गया। प्रशासनिक नियमों के मुताबिक, यदि कोई शासकीय सेवक किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत या न्यायिक रिमांड (जेल) में रहता है तो उसे स्वत: ही निलंबित माना जाता है। इसी प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने यह प्रशासनिक कार्रवाई की है। ?निलंबन अवधि के दौरान आरोपी शिक्षक प्रजापति को शासकीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। हालांकि, जेल से रिहा होने के उपरांत उनके आगामी प्रशासनिक मुख्यालय का निर्धारण विभागीय आदेश के जरिए पृथक से किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें किया नमन

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने लौह पुरूष,



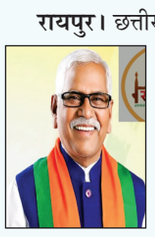
राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार, भारत रत्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती पर आज लोकभवन में उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल डेका ने अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए नमन किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे एवं लोक भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

आज पुष्य नक्षत्र : भूमि भवन, सोना-चांदी, वाहन खरीदी माना जाता है अति शुभ

रायपुर। दीपावली के सात दिन पहले एक नवंबर को खरीदी का महामुहूर्त पुष्य नक्षत्र 22 घंटे रहेगा। ज्योतिर्विदों के अनुसार दीपावली के पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व होता है लेकिन सौ वर्ष में यह पहला मौका है जब साथ में सात शुभ संयोग भी लेकर आया है। बारिश के कारण हालांकि दो दिन कारोबार प्रभावित रहा था लेकिन दीपावली बाजार की शुभ मुहूर्त की खरीदी कल पुष्य नक्षत्र से शुरु होगी जो लक्ष्मी पूजा तक चलेगी। कारोबारियों ने अपने स्तर पर जमकर तैयारी की है। राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाये का असर भी बाजार में रौनक लेकर आयेगी। जैसे कि बताया जा रहा है पुष्य नक्षत्र में सर्वार्थसिद्धि, लक्ष्मीनारायण, श्रीवत्स, मालव्य एवं राजयोग एवं अहोई अष्टमी है। इस दिन रविवार होने से रवि-पुष्य का संयोग भी बन रहा है। यह दिन भूमि-भवन, सोना-चांदी, वाहन सहित सभी चल-अचल खरीदारी के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है।

विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के निधन के बाद दुर्ग में राज्योत्सव कार्यक्रम स्थगित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आयोजित



होने वाला राज्योत्सव का शासकीय कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के निधन के चलते यह निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी मंत्री गजेंद्र यादव ने दी है। मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के निधन के कारण दुर्ग जिले में राज्योत्सव के तहत आयोजित होने वाले शासकीय कार्यक्रम को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि, राज्योत्सव का राज्य स्तरीय और अन्य जिला स्तरीय कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेंगे। बता दें कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का 78 साल की उम्र में शुक्रवार को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक, वे लंबे समय से फेफड़े की बीमारी से पीड़ित थे। उनका इलाज हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में चल रहा था।

राज्योत्सव के बीच रायपुर कलेक्ट्रेट में बड़ी घटना! कर्मचारी ने लगाई परिसर में फांसी

रायपुर। राज्योत्सव की चल रही तैयारियों के बीच शनिवार की सुबह रायपुर कलेक्टोरेट पहुंचे लोग उस वक्त भौचक्के रह गए, जब परिसर की सीढ़ियों में एक व्यक्ति फांसी पर लटका नजर आया। पड़ताल करने पर देखा की सांस टूट चुकी थी, और बेजान शरीर लटका हुआ था। पतासाजी करने पर पता चला कि फांसी पर लटकी लाश कलेक्टोरेट में ही काम करने वाले चौकीदार दिनेश पटेल की है। बताया जा रहा है कि दिनेश पटेल ने अपनी आमदनी से कहीं अधिक का कर्ज ले लिया था। 20 लाख से अधिक कर्जा होने की वजह से वह परेशान था। यह केवल कयास है, क्योंकि मृतक ने कोई सुसाइडल नोट नहीं छोड़ा है। बहरहाल, घटना की सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी यामन देवांगन ने बताया कि सुबह के वक्त घटना की जानकारी मिली है। दिनेश कुमार पटेल (50 साल) पिता प्रभु राम पटेल निवासी श्री साईं नगर, बोरिया खुर्द, आरडीए कॉलोनी, थाना टिकरापारा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। प्रारंभिक जांच में कर्ज और लोन जैसी बात सामने आ रही है। मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

मोहभट्ठा फाटक 4-5 नवंबर को 6 घंटे के लिए रहेगा बंद

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में रेलवे समपार क्रमांक 372 (किमी 732/9-11) मोहभट्ठा गेट पर चौथी रेल लाइन बिछाने का का काम किया जाएगा। इसके चलते दाधापारा-बिल्हा रेलखंड के मोहभट्ठा रेलवे फाटक 4 नवंबर की रात 10 बजे से 5 नवंबर की सुबह 4 बजे तक बंद रहेगा। को कुछ समय के लिए बंद रखा जाएगा। इस दौरान फाटक से सड़क वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। फाटक बंद रहने के दौरान सड़क वाहनों को यहां से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। इस वजह से वाहन चालकों को आने-जाने में परेशानी हो सकती है। रेलवे ने लोगों से तय समय को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। रेलवे ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि फाटक बंद रहने के दौरान आने-जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करें। इससे उन्हें रास्ते में रुकना नहीं पड़ेगा।

सरकार पटवारियों की मांगों पर करेगी विचार : साव

रायपुर। प्रदेशभर में पीवी ऐप के विरोध में पटवारियों का अनिश्चितकालिन हड़ताल जारी है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखना जरूरी है। कर्मचारी जनता की सेवा के लिए नियुक्त हैं, इसलिए उन्हें जनहित को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। उन्होंने पटवारियों से अपील करते हुए कहा कि वह काम पर लौटें और जनता के हितों को प्राथमिकता दें।

चक्रवाती तूफान अर्नब के कारण बरबाद हुई फसलों के नुकसान से किसानों को उभारने के लिए सरकार सर्वे कराएगी। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि जिन किसानों ने नियम और निर्धारित प्रक्रिया के तहत फसल नुकसान की जानकारी दी है, उनका



सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है।

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाले कांग्रेस के प्रदर्शन पर डीसीएम साव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है, उसे जनहित और जनता की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। देश में अराजकता और अस्थिरता पैदा करना कांग्रेस का एजेंडा बन गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है, उनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के प्रति जनता में आक्रोश है, जिसका परिणाम आने वाले समय में दिखाई देगा।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जनहित, राज्य के विकास और देश के विकास से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव का आयोजन हो रहा है और कांग्रेस यहां मौजूद रहने के बजाय दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस अनावश्यक मुद्दों पर आंदोलन कर रही है, जनता सब देख और समझ रही है।

राज्योत्सव 2026 को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर नहीं होने पर सरकार को घेरा। इस मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री साव ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्योत्सव छोड़कर आंदोलन करने जा रहे कांग्रेस के लोग किस मुंह से छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान की बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पर प्रदेश को अपमानित करने और लूटना का काम किया है।

उन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी के मान-सम्मान और गौरव के मुद्दे पर कांग्रेस का रवैया जनता जानती है। छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति सरकार के मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, इसके लिए कांग्रेस से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है।

मंगलम हुंडई ने रायपुर में पहली हुंडई बेयॉन की डिलीवरी के साथ रचा इतिहास

रायपुर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हुए, रायपुर की अग्रणी और भरोसेमंद ऑटोमोबाइल डीलरशिप मंगलम हुंडई ने छत्तीसगढ़ में हुंडई बेयॉन की पहली डिलीवरी की घोषणा की है। यह डिलीवरी देवपुरी, रायपुर स्थित मुख्य शोरूम में की गई। छत्तीसगढ़ में हुंडई बेयॉन के पहले प्राउड ओनर दलजीत बग्गा बने हैं। इस विशेष अवसर पर मंगलम हुंडई के जीएम - सेल्स, राज मुराव ने श्री बग्गा को चाबी सौंपकर इस पल को यादगार बनाया।

अपने कंटेम्पररी डिज़ाइन, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, शानदार परफॉरमेंस और बेहतरीन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के लिए यह गाड़ी विश्व स्तर पर पहचानी जा रही है। हुंडई बेयॉन ने ऑटोमोबाइल बाजार में आते ही ग्राहकों का दिल जीत लिया है। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर इस बेहतरीन गाड़ी का उतरना राज्य के ऑटोमोबाइल लवर्स के लिए एक नए और प्रीमियम युग की शुरुआत है।

इस मौके पर डीलरशिप ने कहा-हमें अत्यंत हर्ष है कि छत्तीसगढ़ की पहली हुंडई बेयॉन की डिलीवरी हमारे शोरूम से हो रही है। हम दलजीत बग्गा जी का मंगलम हुंडई परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं तथा उनके सुगम एवं सुरक्षित सफर की कामना करते हैं। हमारे लिए ग्राहकों का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

सीएम हेल्पलाइन 1076 पर एक कॉल से रिया को मिला छात्रावास, पढ़ाई को मिली नई राह

■ 90 प्रतिशत से अधिक आवेदक निराकरण से संतुष्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण का भरोसेमंद माध्यम बन रही है। बलरामपुर जिले के ग्राम मौली की मेधावी छात्रा कुमारी रिया को हेल्पलाइन पर की गई एक कॉल से कक्षा 9वीं की पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिला। रिया ने 88.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, लेकिन छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलने से उसकी पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका थी। पिता श्री अजय प्रसाद अगरिया ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर समस्या दर्ज कराई। दस दिनों के भीतर आदिम जाति विकास विभाग ने प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास, वाड्रफनगर में रिया को सीट आवंटित कर दी।

बलरामपुर जिले में हेल्पलाइन के माध्यम से हुए निराकरणों का आकलन मुख्यमंत्री सुशासन फेलो श्री मध्यम दुबे ने अपनी रिपोर्ट में किया है। यह रिपोर्ट कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में तैयार की गई। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप, छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग की पहल है, जिसका संचालन आईआईएम रायपुर के सहयोग से किया जा रहा है। आईआईएम रायपुर में तीन माह के प्रशिक्षण के बाद दूसरे बैच के 36 फेलो नीति क्रियान्वयन और सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने के लिए विभिन्न जिलों में तैनात किए गए हैं। श्री दुबे बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में पदस्थ हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने वाले 90 प्रतिशत से अधिक आवेदक मिले समाधान से संतुष्ट हैं। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को हेल्पलाइन के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल प्रकरण बंद करना नहीं, बल्कि आवेदक की समस्या का वास्तविक समाधान करना होना चाहिए।

रिपोर्ट में दर्ज उदाहरणों के अनुसार, ग्राम बरदर के किसान श्री मुकेश के खेत की खराब बिजली लाइन दो दिनों में ठीक कर आपूर्ति बहाल की गई, जिससे सिंचाई प्रभावित नहीं हुई। ग्राम चिनिया में श्री बाउलाल सिंह की शिकायत पर बंद सौर पेयजल संयंत्र सुधारा गया और गांव में पेयजल आपूर्ति फिर शुरू हुई। ग्राम बचवार की प्राथमिक शाला में पेयजल, नल और शौचालय से जुड़ी अव्यवस्थाओं को भी दो दिनों में दुरुस्त किया गया। महिला एवं बाल विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई की गई। ग्राम जूनामाकड़ के ढाई वर्षीय ईथन कुजूर का विवरण पोषण ट्रैकर ऐप में अद्यतन कर उसे रेडी-टू-ईट पूरक पोषण आहार दिलाया गया। ग्राम बरदर की श्रीमती माया गुप्ता को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर मिलने वाला लाभ दिलाया गया। श्रीमती दुर्गावती कनौजिया की महतारी वंदन योजना से जुड़ी ई-केवाईसी पूरी कराई गई।

देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकीकरण के महान शिल्पकार थे सरदार पटेल : मुख्यमंत्री

साय ने लौह पुरुष वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज यहाँ सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में भारत रत्न, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल के ऐतिहासिक योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल भारतीय एकता और अखंडता के महान शिल्पकार थे। उन्होंने अपने अदम्य साहस, दृढ़ इच्छाशक्ति और कुशल नेतृत्व से स्वतंत्रता के बाद देश की सैकड़ों रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक सशक्त और अखंड भारत की नींव रखी। राष्ट्र निर्माण में उनका यह असाधारण योगदान भारतीय इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरदार पटेल का संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने, अनुशासन,



कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और देश की एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, सामूहिक प्रयास और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण से बड़ी से बड़ी चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज देश विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। सरदार पटेल के विचार और आदर्श इस राष्ट्रीय संकल्प को और अधिक सशक्त बनाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस केवल सरदार पटेल के महान योगदान को स्मरण करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को अक्षुण्ण बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का भी दिन है। भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और समुदायों को एकता के सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ना ही सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे सरदार वल्लभभाई पटेल के आदर्शों को आत्मसात करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर एक सशक्त, समरस और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए, ताकि विकसित भारत के निर्माण में हमारा प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा सके।

हैदराबाद से रायपुर पहुंचा विधायक कोर्सेवाड़ा का पार्थिव शरीर

रायपुर। अहिवारा से भाजपा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का पार्थिव शरीर हैदराबाद से रायपुर पहुंच गया है। रायपुर एयरपोर्ट परिसर स्थित स्टेट हैंगर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रदेश के कई मंत्री, भाजपा नेता और जनप्रतिनिधियों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पार्थिव शरीर को दुर्ग-भिलाई के लिए रवाना कर दिया गया। उनका अंतिम संस्कार दुर्ग जिले के गुंडरदेही क्षेत्र स्थित पैतृक गांव भेण्ड्रा में किया जाएगा।

स्टेट हैंगर में डिप्टी सीएम अरुण साव, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री रामविचार नेताम और भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई विधायकों ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। डोमनलाल कोर्सेवाड़ा पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। वे फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे और हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 78 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के साथ दुर्ग-भिलाई और प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में शोक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है।

12 अगस्त 1948 को जन्मे डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की थी। उन्होंने बीएड भी किया था। राजनीति में आने से पहले वे शिक्षा विभाग में व्याख्याता थे। वर्ष 1998 में रिटायर होने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 1999 में वे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के तत्कालीन सांसद के निजी सहायक के रूप में भी काम कर चुके थे।

रायपुर मंडल के 11 सदस्य सेवानिवृत्त



रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल के विभिन्न विभागों में कार्यरत रेल परिवार के 11 सदस्य अक्टूबर में अपनी गौरवशाली रेल सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सामान्य सेवानिवृत हुए।

इस समारोह में मंडल रेल प्रबंधक श्री दयानन्द, सहायक कार्मिक अधिकारी महेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त कर्मी एवं उनके परिजन, कल्याण निरीक्षक तथा बंदोबस्त अनुभाग के कर्मचारी एवं सभी विभागों से संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। मंडल के सेवानिवृत्त होने वाले 11 रेलकर्मियों में दो यांत्रिकी विभाग से 02, इंजीनियरिंग विभाग से 02, परिचालन विभाग से 04, विद्युत् विभाग से 01 , सिग्नल एंड टेलिकॉम का 02 कर्मचारी शामिल है।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सम्मलेन कक्ष में आयोजित समारोह में समस्त सेवानिवृत्त कर्मियों को विदाई दी गई। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का समस्त भुगतान प्रमाण-पत्र दिया गया। ई-पेमेंट के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कुल राशि रुपये 59609434 का भुगतान किया गया। पेंशन भुगतान आदेश, सेवानिवृत्त कर्मचारी का पहचान पत्र एवं कर्मचारियों एवं आश्रितों का पास कार्ड 30 नवजढको प्रदान किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक ने संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा के दौरान अपने दायित्यो का निर्वहन अच्छे से करने पर बधाई दी तथा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए सेवानिवृत्त जीवन को अपने परिवार एवं रिश्तेदारों के साथ आनंदपूर्वक व्यतीत करने की बात कही, साथ ही सेवानिवृत्ति के दौरान मिली राशि को सही जगह निवेश करने की सलाह दी।

पॉवर कंपनी से सीई तिवारी व श्रीवास्तव सहित 4 कर्मियों को भावभीनी विदाई



रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी से मुख्य अभियंता राजेश कुमार तिवारी एवं मुख्य अभियंता अखिलेश चंद्र श्रीवास्तव सहित कुल चार अधिकारी-कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। पॉवर कंपनीज के मुख्यालय सेवा भवन में आयोजित समारोह में तिवारी एवं श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत तिवारी एवं श्रीवास्तव ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए अपने सेवायात्रा में मिले सहयोग के लिए प्रबंधन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ई डी (एच.आर) आर.पी.नामदेव, जनरेशन कंपनी के सीई (एच.आर) शशिधर द्विवेदी एवं ट्रांसमिशन कंपनी की सीई (एच.आर) श्रीमती रश्मि वर्मा ने सेवानिवृत्तजनों को नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी।

इसी तरह छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने मुख्य अभियंता राजेश कुमार तिवारी, निज सचिव नीरज कुमार मिश्रा एवं सहायक प्रबंधक सुधीर गनपत राव राजिमवाले को सम्मानित कर भावभीनी विदाई दी। समारोह में एमडी शुक्ला ने कहा कि सेवानिवृतजनों के समर्पण, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं अनुभवों से पॉवर कंपनी के विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिली हैं। संचालन डीजीएम गोविन्द पटेल, सहायक प्रबंधक श्रीमती अनामिका मंडावी ने व आभार प्रदर्शन अधीक्षण अभियंता पंकज चौधरी ने किया।

डीएमएफ घोटाला : ईडी ने सतपाल-मंदीप समेत 17 आरोपियों के खिलाफ पूरक चालान पेश किया

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने मामले में करीब 31.70 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इसके साथ ही 17 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर में पूरक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की गई है।

ईडी की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को प्रिविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) जारी किया गया, जबकि 30 अक्टूबर को विशेष न्यायालय में पूरक अभियोजन शिकायत पेश की गई। इसमें सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत 15 अन्य आरोपियों को शामिल किया गया है।

ईडी की जांच में सामने आया है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए निर्धारित डीएमएफ की राशि का सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) के माध्यम से सरकारी अधिकारियों, एजेंटों और बिचौलियों के संगठित नेटवर्क ने इस घोटाले को अंजाम दिया। आरोप है कि डीएमएफ की राशि से ऐसे कार्यों और आपूर्तियों को प्राथमिकता दी गई, जिनमें खरीद की कीमतें बढ़ाकर दिखाई गईं और इसके बदले बड़े पैमाने पर अवैध कमीशन वसूला गया।

ईडी के मुताबिक, एजेंट और बिचौलिये रेट कॉन्ट्रैक्ट धारक कंपनियों को जारी खरीद आदेशों की मूल राशि पर 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन वसूलते थे। इस कमीशन का बड़ा हिस्सा डीएमएफ फंड आवंटित करने,



खरीद आदेश जारी करने और भुगतान जारी कराने के बदले सरकारी अधिकारियों तथा प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाया जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि कमीशन की रकम नकद और बैंकिंग माध्यमों से एकत्र की जाती थी। इसके बाद विभिन्न कंपनियों और बैंक खातों के जरिए रकम को अलग-अलग स्तरों पर स्थानांतरित कर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। बीज निगम के माध्यम से डीएमएफ के अलावा अन्य मदों से होने वाली खरीदी में भी इसी तरह कमीशन वसूले जाने की बात सामने आई है।

ईडी की जांच में सतपाल सिंह चाबड़ा को सिंडिकेट का प्रमुख बिचौलिया और वित्तीय समन्वयक बताया गया है। आरोप है कि उसने चुनिंदा विक्रेताओं को काम दिलाने, खरीद आदेश जारी कराने, भुगतान करवाने और अवैध कमीशन के संग्रह व वितरण में अहम भूमिका निभाई। ईडी ने सतपाल सिंह चाबड़ा को 1 सितंबर 2026 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था।

ईडी के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ लगभग 35 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय का पता लगाया गया है। इसके विरुद्ध इस कार्रवाई में करीब 31.70 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस मामले में अब तक आईएएस अधिकारी रानू साहू समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, मामले में अब तक लगभग 50 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं।

ईडी ने स्पष्ट किया है कि डीएमएफ फंड के दुरुपयोग, अवैध कमीशन के संग्रह एवं वितरण और अपराध से अर्जित राशि को वैध बनाने में शामिल सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य एजेंटों की भूमिका की जांच अभी जारी है। मामले में आगे भी कार्रवाई की जा सकती है।

पंजाब विस चुनाव : नशा और कानून-व्यवस्था होंगे मुख्य मुद्दे

इकबाल सिंह चन्नी

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों का माहौल बनना शुरू हो गया है। इन चुनावों में नशों का संकट, बिगड़ती कानून-व्यवस्था और राज्य पर बढ़ते कर्ज का बोझ मुख्य राजनीतिक मुद्दे बन सकते हैं। बेरोजगारी, किसानी संकट और औद्योगिक विकास की मंदी भी इनसे जुड़े अहम सवाल हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए यह 5 सालों की कारगुजारी का इम्तिहान होगा, जबकि कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के लिए लोगों के सामने अपना बदला हुआ नजरिया पेश करने की चुनौती होगी। नशों का मुद्दा इस बार चुनावी चर्चा के केंद्र में रहने के संकेत दे रहा है। 2022 के चुनावों के समय आम आदमी पार्टी ने नशों के खात्मे का वादा किया था। सरकार बनने के बाद नशा मुक्त पंजाब के लिए कई मुहिमें चलाई गईं लेकिन नशों की उपलब्धता और युवाओं में इसकी लत के बारे में चिंताएं जारी हैं। अक्तूबर 2026 में नशों विरुद्ध आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की मानसा में हत्या ने इस मुद्दे को फिर से राजनीतिक केंद्र में ला दिया है। चुनावों में असल सवाल यह होगा कि नशों की सप्लाई करने वाले बड़े नैटवर्क को किस हद तक तोड़ा गया, तस्करों के वित्तीय स्रोतों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और नशा छुड़ाऊ इलाज व पुनर्वास की सुविधाओं में कितना इजाफा हुआ। सिर्फ गिरफ्तारियों या ऐलानों की गिनती से नशा मुक्त पंजाब का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। नशों के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ नशे की लत के शिकार नौजवानों का इलाज भी सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। दूसरा बड़ा मुद्दा कानून-व्यवस्था का है। गैंगस्टरों की गतिविधियों, फिरौती, गोलीबारी, गैर-कानूनी हथियारों और संगठित अपराध की घटनाएं लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा करती हैं। व्यापारियों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल देना किसी भी सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। विरोधी पार्टियां इन घटनाओं को सरकार की नाकामी के तौर पर पेश करेंगी, जबकि सरकार को अपनी कार्रवाइयों के नतीजे सामने रखने होंगे। हर घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई और आपराधिक नैटवर्क को तोडना लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल पंजाब की वित्तीय स्थिति का है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में राज्य का वित्तीय घाटा राज्य के कुल घरेलू उत्पाद का 4.1 फीसदी, यानी लगभग 39,971 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। राजस्व घाटा भी लगभग 21,955 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ये बजट अनुमान हैं, अंतिम खर्चे के आंकड़े नहीं। फिर भी यह राज्य के सामने खड़ी वित्तीय चुनौती की गंभीरता को दर्शाते हैं। कर्ज की किस्तों और ब्याज की अदायगी के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार के लिए उपलब्ध स्रोतों पर दबाव पड़ता है। सरकार को बताना होगा कि आमदनी बढ़ाने, औद्योगिक निवेश लाने और खर्चों को संतुलित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। यह मुद्दा सिर्फ आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल को भी यह स्पष्ट करना होगा कि वे लोक-कल्याण की योजनाओं को जारी रखते हुए पंजाब की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे। कांग्रेस के लिए चुनौती सरकार की कमजोरियों को उजागर करने के साथ अपनी संगठनात्मक एकजुटता और बदली हुई नीति पेश करने की है। भाजपा को नशों, सुरक्षा और आर्थिक प्रबंधन के बारे में अपना पक्ष रखने के साथ किसानों, ग्रामीण मतदाताओं और सिख भाईचारे में भरोसा बढ़ाना पड़ेगा।

विधान परिषद चुनावों के परिणामों के महत्वपूर्ण सियासी संदेश

कमलेश पांडे

चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों के मिले-जुले परिणामों में भले ही भाजपा-राजग को बढ़त मिली हो, लेकिन उत्तरप्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भाजपा -राजग को विपक्षी दलों द्वारा कड़ी टक्कर मिली है, जबकि कर्नाटक की चारो सीट जीतकर भाजपा राजग ने वहां की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को जबर्दस्त सियासी पटखनी दी है। वहीं, कांग्रेस के सामने संगठनात्मक चुनौती खड़ी हुई है। उसे एक मात्र नागपुर स्नातक सीट मिली है। लेकिन आरएसएस मुख्यालय होने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में मिली कांग्रेस को यह जीत इस बात का संकेत है कि सवर्ण वोटर अब भाजपा की अतिवादी दलित-ओबीसी नीतियों से ऊब चुके हैं और कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार को जितवाने से भी उन्हें गुरेज नहीं है।

यदि राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सपा की मजबूती और बिहार में जन सुराज का आगाज—बीजेपी-एनडीए को सवर्ण वोटरों की उदासीनता के दृष्टिगत सावधान कर रहे हैं। भले ही चार राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों के नतीजे 28 अक्टूबर 2026 को सामने आए, लेकिन इन मिले जुले परिणामों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारतीय राजनीति की एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है।

जहां भाजपा और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगियों ने कुल 28 सीटों में से 16 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को एक मात्र सीट मिली है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई, तो बिहार में जन सुराज को पहली सफलता मिली। महाराष्ट्र में भी मुकाबला पूरी तरह एकतरफा नहीं रहा और भाजपा नीत महायुति गठबंधन को कांग्रेस नीत महा विकास अघाड़ी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार से कड़ी टक्कर मिली है। इन नतीजों का महत्व केवल जीत और हार की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक दलों की संगठनात्मक क्षमता, स्थानीय नेतृत्व, शिक्षक एवं स्नातक मतदाताओं से जुड़ाव और विपक्षी गठबंधनों के भीतर प्रतिस्पर्धा के बारे में भी संकेत देते हैं।

जहां तक चारों राज्यों के चुनावी गणित का सवाल है तो यह जान लीजिए कि गत 23 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान परिषद की कुल 28 सीटों के



लिए मतदान हुआ, जिसकी मतगणना 28 अक्टूबर को हुई। उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 8, कर्नाटक की 4 और महाराष्ट्र की 5 यानी कुल 28 सीटों के नतीजे आए। उत्तर प्रदेश की कुल 11 सीटें में से भाजपा को 6 और समाजवादी पार्टी (सपा) को 5 सीटों पर जीत मिली, यानी मुकाबला कांटे का रहा। वहीं, बिहार की कुल 8 सीटों में भाजपा को 3 और जनता दल (यूनाइटेड) को 1 सीट मिली। यानी भाजपा नीत राजग 8 सीटों में से 4 सीटें जितने में कामयाब रहा। जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को 1, जन सुराज पार्टी को 1 और निर्दलीय को 2 सीटें मिली हैं। इस प्रकार बिहार में भाजपा सबसे अधिक तीन सीटें जीतने वाली पार्टी रही। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी दो सीटें हासिल कीं। इनकी भी पृष्ठभूमि भाजपाई ही रही है।

वहीं, कर्नाटक की कुल 4 सीटों में भाजपा को 3 सीटें और जनता दल (सेक्युलर) को 1 सीट मिली। यहां की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस 0 पर आऊट हो गई। कर्नाटक में भाजपा-जद(एस) गठबंधन ने चारों सीटें जीत लीं। वहीं, महाराष्ट्र की कुल 5 सीटों में भाजपा को 1, शिवसेना (महायुति) को 1, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। वहीं, महाराष्ट्र विधान परिषद की नागपुर स्नातक निर्वाचन सीट के चुनाव आयोग और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सुधाकर कोहले को शिकस्त दी है।

चार राज्यों में 16 सीटें जीतना भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए संगठनात्मक सफलता का संकेत है। विशेष रूप से कर्नाटक में चारों सीटों पर जीत ने विपक्षी गठबंधन के समन्वय और कांग्रेस की स्थानीय चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, इन परिणामों को सीधे विधानसभा चुनावों के जनादेश के बराबर मानना उचित नहीं होगा। भाजपा के सामने अब इस सफलता को व्यापक जनसंपर्क, स्थानीय समस्याओं के समाधान और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी से जोड़ने की चुनौती है।

कांग्रेस द्वारा चारों राज्यों में मात्र एक सीट जीत पाना उसके लिए गंभीर राजनीतिक सवाल पैदा करता है। खासकर कर्नाटक में उसकी अपनी सरकार है, फिर भी पार्टी किसी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी। इसके तीन संभावित सबक हैं- एक, स्थानीय स्तर पर संगठन और उम्मीदवार चयन की समीक्षा आवश्यक है। दो, शिक्षक एवं स्नातक जैसे विशिष्ट मतदाता वर्गों से निरंतर संवाद जरूरी है। तीन, गठबंधन की राजनीति के साथ-साथ अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को भी मजबूत करना होगा। हालांकि, विधान परिषद चुनावों के मतदाता सीमित और विशिष्ट वर्गों से आते हैं। इसलिए इन नतीजों के आधार पर कांग्रेस के समूचे जनाधार के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

उत्तर प्रदेश के नतीजे खास महत्व रखते हैं, क्योंकि राज्य में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। भाजपा ने कई सीटों पर अपना प्रभाव बनाए रखा, लेकिन सपा ने पांच सीटें जीतकर यह दिखाया कि वह विधान परिषद के चुनावों में भी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखती है। सपा को वाराणसी की दो सीटों पर सफलता मिलना भी उल्लेखनीय रहा। इसका सियासी अर्थ यह है कि दोनों दलों को अपने संगठन, स्थानीय नेतृत्व और मतदाता संपर्क पर ध्यान देना होगा। फिर भी, विधान परिषद के सीमित मतदाता वर्ग और विधानसभा के व्यापक मतदाता वर्ग में अंतर है। इसलिए इन नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव का निश्चित संकेत नहीं माना जा सकता।

बिहार के दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के निवर्तमान विधान परिषद सदस्य मदन मोहन झा को 324 मतों से हराया। इससे जन सुराज को विधान परिषद में पहली चुनावी सफलता मिली। पटना शिक्षक सीट पर राजद ने भाजपा के नवल किशोर यादव को हराया, जबकि सारण में निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज ने जीत दर्ज की।

इन परिणामों से तीन बातें सामने आती हैं- एक, नए राजनीतिक विकल्प की गुंजाइश: जन सुराज ने सीमित लेकिन महत्वपूर्ण चुनावी सफलता हासिल की। दो, स्थानीय असंतोष का महत्व: पुराने और स्थापित उम्मीदवारों को भी मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तीन, निर्दलीय उम्मीदवारों की प्रासंगिकता- स्थानीय पहचान और मतदाताओं से सीधा संपर्क दलगत समर्थन के अतिरिक्त भी भूमिका निभा सकता है। जन सुराज के लिए असली चुनौती इस सफलता को दूसरे क्षेत्रों में भी संगठनात्मक विस्तार में बदलना होगी।

महाराष्ट्र में महायुति और विपक्षी गठबंधन के बीच मुकाबला मिश्रित रहा। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (एसपी) ने पुणे स्नातक और छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। वहीं भाजपा और महायुति के अन्य सहयोगियों को भी सफलता मिली। जबकि नागपुर स्नातक सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी। यह परिणाम बताता है कि राज्य की राजनीति को केवल एक दल बनाम दूसरे दल के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। गठबंधन, स्थानीय उम्मीदवार, क्षेत्रीय नेतृत्व और मतदाता समूहों की प्राथमिकताएं भी परिणामों को प्रभावित करती हैं।

विधान परिषद चुनावों में केवल निर्धारित शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के पात्र मतदाता मतदान करते हैं। इन चुनावों में मतपत्रों का इस्तेमाल होता है, ईवीएम का नहीं। इसलिए इन परिणामों से संगठनात्मक ताकत, स्थानीय असंतोष और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन पूरे राज्य या देश की जनता की राजनीतिक पसंद का सीधा अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

इसके बावजूद, परिणाम तीन व्यापक प्रश्न जरूर खड़े करते हैं: एक, क्या सत्तारूढ़ दल अपनी स्थानीय उपलब्धियों और संगठन को प्रभावी चुनावी समर्थन में बदल पा रहे हैं? दो, क्या विपक्षी दल स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार और साझा रणनीति तैयार कर पा रहे हैं? तीन, क्या नए राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार स्थापित दलों के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनौती बन सकते हैं?

वस्तुत: चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों का सबसे बड़ा सियासी संदेश यह है कि भाजपा-राजग को समग्र बढ़त मिली है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कायम है। उत्तर प्रदेश में सपा की सफलता, बिहार में जन सुराज का प्रवेश, कर्नाटक में कांग्रेस की हार और महाराष्ट्र में मिला-जुला परिणाम—ये सभी अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं। किसी एक राज्य की सफलता को दूसरे राज्य में दोहराया हुआ जनादेश मानना उचित नहीं होगा। अंतत: राजनीतिक दलों के लिए इन चुनावों की उपयोगिता इसी में है कि वे मतदाताओं के संदेश को समझें, संगठनात्मक कमियों की पहचान करें और जनता के मुद्दों पर अपनी जवाबदेही बढ़ाएं।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय



22. नागार्जुन का शून्यवाद

गतांक से आगे...

इनमें से लङ्कावतार सूत्र में शून्यवाद और विज्ञानवाद का मिला-जुला सा वर्णन पाया जाता है। परन्तु शून्यवाद के दार्शनिक रूप का प्रवत्तक प्रथम आचार्य नागार्जुन को माना जाता है। भारतीय इतिहास के सत्र से महान् गिने चुने दार्शनिकों में नागार्जुन का मूद्धन्य स्थान है।

संम्भवत: वह कनिष्क के समय में हुआ यद्यपि निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। परन्तु उस की तिथि ईसा की द्वितीय शताब्दी से पहिले ही होगी, क्योंकि गोतम के न्यायसूत्रों में शून्यवाद का खण्डन किया गया है, और न्यायसूत्रों की तिथि ईसा की तृतीय सदी के बाद रखना सम्भव नहीं है।

नागार्जुन का मूल ग्रन्थ जिसमें शून्यवाद की स्थापना की गयी माध्यमिककारिका या माध्यमिकसूत्र है।

इस में सूत्र के समान संक्षिप्त 400 कारिकाओं में दार्शनिक विषय का प्रतिपादन किया गया है। सारे संस्कृत साहित्य में सूत्र रूप कारिका प्रणाली का प्रथम प्रवत्तक नागार्जुन ही प्रतीत होता है। पीछे इसी शैली का कुमारिल आदि ने अनुसरण किया।

इन कारिकाओं पर स्वयं नागार्जुन ने अकुतोभया नामक टीका लिखी थी जो इस समय मूल संस्कृत रूप में अप्राप्य है।

इस समय चन्द्रकीर्ति की प्रसन्नपदा टीका ही कारिकाओं के समझने में हमारा आधार है और वह महत्त्वपूर्ण टीका है। स्वत: चन्द्रकीर्त्ति का बौद्ध दार्शनिक साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है।

हर्ष की बात है कि जागार्जुन की माध्यमिक कारिका मूलमाध्यमिककारिका के नाम से चन्द्रकीर्ति की प्रसन्नपदा टीका सहित डी. ला वाली पूसिन् द्वारा सम्पादित होकर लेनिनग्रेड (पेट्रोग्रेड) की निब्लोथिका बुद्धिका सीरीज में प्रकाशित हो चुकी है।

क्रमश: ...

भगवान विष्णु का शयन और उत्थान, श्रीहरि के योगनिद्रा से जागते ही सृष्टि में पुनः गति आती है

आशुतोष गर्ग

भगवान विष्णु के शयन का जब समय आता है, तब वह वैकुंठ धाम में स्थित अपने नारायणाश्रम में प्रवेश करते हैं। वहां पहुंचकर वह अपने सभी आयुधों का त्याग कर देते हैं। उनका शयनागार समुद्र के समान विशाल और दिव्य है। देवताओं और असुरों के लिए भी वहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। वहां सूर्य, चंद्रमा और वायु की भी पहुंच नहीं है। भगवान पद्मनाभ के सच्चिदानंदमय स्वरूप की दिव्य ज्योति ही उस धाम को प्रकाशित करती है।

जो भगवान विराट स्वरूप में संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, वही अब वहां पहुंचकर समस्त प्राणियों की कर्मवासनाओं को अपने भीतर समेटकर विश्राम करने लगते हैं। योगनिद्रा उनकी सेवा में उपस्थित होती है। भगवान समुद्र और मेघों के जल से शीतल दिव्य शय्या पर शयन करते हैं। उनके इस शयन को उस महान प्रलयकाल से जोड़ा गया है, जब संपूर्ण संसार एकार्णव में विलीन हो जाता है और केवल भगवान नारायण ही शेष रहते हैं। शयन करते हुए भगवान की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है। सूर्य के समान चमकने वाला वह सहस्रदल कमल ब्रह्मा जी का आसन बनता है। भगवान स्वयं योगनिद्रा में होते हुए भी सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन करते रहते हैं। उनके भीतर स्थित कर्म-संस्कार मानो सृष्टि के पुनः आरंभ होने का संकेत देते हैं। उनके मुख से निकलने वाली श्वास से विभिन्न प्रकार की प्रजा उत्पन्न होती रहती है, जो अपने-अपने निर्धारित कर्म और धर्म का पालन करती है।



भगवान विष्णु की यह योगनिद्रा साधारण निद्रा नहीं है। उनके इस रहस्यमय स्वरूप को स्वयं ब्रह्मा जी और महान ब्रह्मर्षि भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। वे यह जानने में असमर्थ रहते हैं कि परमात्मा कब जागते हैं, कब सोते हैं और कब बिना किसी बाहरी चेष्टा के भी संपूर्ण जगत का संचालन करते हैं। देवता भी उनके जन्म, कर्म और स्वरूप के रहस्य को जानने का प्रयास करते रहते हैं, किंतु उनकी लीला का कोई अंत नहीं पा सकते।

भगवान विष्णु ही वेद, यज्ञ और यज्ञ के सभी अंग हैं। यज्ञों के माध्यम से जिस परम गति की प्राप्ति बताई गई है, वह भी उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति है।

उनके शयनकाल में मंत्रों से पवित्र यज्ञकर्मों का अनुष्ठान नहीं किया जाता। जब शरद ऋतु में भगवान मधुसूदन जागते हैं, तब वाजपेय आदि यज्ञों का पुनः आरंभ होता है। प्रभु के शयनकाल में देवराज इंद्र प्रजापालन का कार्य संभालते हैं और वर्षा ऋतु से संबंधित उपाकर्म, श्राद्ध तथा तर्पण आदि कर्म करवाते हैं। प्रभु की योगनिद्रा से जुड़ी माया ही संसार में सामान्य निद्रा के रूप में भी दिखाई देती हैं। यह तमोमयी शक्ति रात्रि और अंधकार के रूप में प्राणियों को अपने प्रभाव में ले लेती है। मनुष्य दिनभर के परिश्रम के बाद निद्रा में चला जाता है और कुछ समय के लिए संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। सामान्य निद्रा जागने के बाद समाप्त हो जाती है, किंतु मृत्यु के समय यही शक्ति प्राणों का अंत करने वाली बन जाती है। श्रीनारायण के अतिरिक्त कोई भी देवता इस शक्ति को पूरी तरह धारण करने में समर्थ नहीं है। भगवान के शरीर से प्रकट हुई यह माया काल की सहचरी और संसार के मोह का कारण है।

भारत की रक्षा कूटनीति ने पूरी दुनिया में छोड़ा प्रभाव

नीरज कुमार दुबे

राजनाथ सिंह की रक्षा कूटनीति ने अमेरिका के सामने भारत की सुरक्षा चिंताओं को जिस दृढ़ता और दोटूक अंदाज में रखा है, उसने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने के मुद्दे पर वाशिंगटन को भी असहज स्थिति में ला खड़ा किया। एफ-16 लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिकी सहायता पैकेज पर भारत की कड़ी आपत्ति और पाकिस्तान को दी जाने वाली संवेदनशील तकनीक के तीसरे देश तक पहुंचने की आशंका उठाकर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब अपनी सुरक्षा के सवाल पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।

आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों के खिलाफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सख्त संदेश इस बात का संकेत है कि भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। देखा जाये तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर साबित किया है कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन में भारत की रक्षा कूटनीति केवल बैठकों और औपचारिक बयानों तक सीमित नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की स्पष्ट पैरवी करने, मित्र देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत की शर्तों को प्रभावी ढंग से सामने रखने का माध्यम भी है।

हम आपको बता दें कि फिलीपींस के सेबू में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने अमेरिका के सामने पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों के लिए सहायता पैकेज देने का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकातों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने भारत का पक्ष इतनी स्पष्टता से रखा कि वाशिंगटन के लिए पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता के दुष्परिणामों पर जवाब देना और इस्लामाबाद का बचाव करना मुश्किल हो गया। अमेरिका के रक्षा मंत्री



पीट हेगसेथ के साथ बातचीत में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के एफ-16 कार्यक्रम से जुड़े सहायता पैकेज पर भारत की गंभीर चिंता व्यक्त की। हम आपको बता दें कि अमेरिका का 64.9 करोड़ डॉलर का यह पैकेज पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की परिचालन क्षमता और रखरखाव को मजबूत करने से जुड़ा है। इसमें एवियोनिक्स सुधार, तकनीकी उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, प्रशिक्षण, सिमुलेटर और लॉजिस्टिक सहायता जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

भारत की आपत्ति का मूल प्रश्न यही है कि पाकिस्तान को मिलने वाली ऐसी सैन्य सहायता का वास्तविक इस्तेमाल किस उद्देश्य से होगा और इसका दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने वाले किसी भी कदम को नई दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में देखती है।

राजनाथ सिंह ने अमेरिकी पक्ष को इस बात के लिए भी आगाह किया कि पाकिस्तान को दी जाने वाली संवेदनशील सैन्य तकनीक किसी तीसरे देश तक पहुंच सकती है। देखा जाये तो यह चिंता केवल भारत-पाकिस्तान संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी सुरक्षा, हथियारों के प्रसार और व्यापक क्षेत्रीय सामरिक संतुलन से भी जुड़ी है।

राजनाथ सिंह की कूटनीतिक पहल का महत्व इस बात में है कि भारत ने अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सीधे अमेरिकी नेतृत्व के सामने स्पष्टता और दृढ़ता के साथ रखा है। भारत ने यह संदेश दिया है कि रणनीतिक साझेदारी अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर वह चुप्पी नहीं साधेगा।

राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ बातचीत के दौरान आतंकवाद के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति पर जोर दिया। उनका संदेश स्पष्ट था कि आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण या वित्तीय सहायता देने वाले देशों के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय का रवैया सुसंगत और कठोर होना चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी सीमा पार आतंकवाद से मुकाबले में भारत के प्रति समर्थन दोहराया। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक आधार है, क्योंकि आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग तभी प्रभावी हो सकता है जब सुरक्षा संबंधी चिंताओं को केवल बयानों में नहीं, बल्कि व्यावहारिक नीतियों में भी जगह मिले।

इसके अलावा, भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी के दस वर्षीय ढांचे की समीक्षा, सैन्य आदान-प्रदान, समुद्री सुरक्षा और रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों देश अपने सहयोग को व्यापक रणनीतिक दिशा देना चाहते हैं। भारत का प्रयास है कि अमेरिका के साथ साझेदारी मजबूत बनी रहे, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने जैसे मुद्दों पर भारतीय चिंताओं को नजरअंदाज न किया जाए।

साथ ही राजनाथ सिंह की कूटनीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी बातचीत है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ चर्चा में समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक जहाज निर्माण, डिजाइन और माइन काउंटरमेजर्स क्षमताओं में सहयोग जैसे मुद्दे शामिल रहे। जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की विनिर्माण क्षमता को जोड़ने की संभावनाएं रक्षा औद्योगिक सहयोग को नई दिशा दे सकती हैं।

जापान के साथ वायुसेना सहयोग बढ़ाने और रक्षा उद्योग से जुड़ी कंपनियों के बीच संपर्क मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। यह सहयोग केवल सैन्य अभ्यासों तक सीमित नहीं है; इसका उद्देश्य दीर्घकाल में रक्षा क्षमताओं, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना भी है।

ऑस्ट्रेलिया के उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स के साथ बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग की समीक्षा की और आपसी समन्वय बढ़ाने पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने उन्हें फरवरी 2027 में बेंगलुरु में प्रस्तावित एयरो इंडिया में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।

इसी बीच राजनाथ सिंह की जापानी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ तस्वीर तथा उनका संदेश, 'JAI: Japan, Australia, India', विशेष राजनीतिक और रणनीतिक महत्व रखता है। यह तीनों देशों के बीच सहयोग, विश्वास और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा हितों का प्रतीक है। एक स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित हिंद-प्रशांत भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी का प्रमुख आधार बना हुआ है।

इन बैठकों को एक साथ देखने पर राजनाथ सिंह की रक्षा कूटनीति के दो महत्वपूर्ण आयाम सामने आते हैं। एक तो अमेरिका जैसे प्रमुख रणनीतिक साझेदार के सामने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने के दुष्परिणामों पर स्पष्ट आपत्ति दर्ज कराना। दूसरा, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे विश्वसनीय साझेदारों के साथ रक्षा, तकनीक, समुद्री सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाना।

यही सक्रिय रक्षा कूटनीति की विशेषता है। भारत किसी एक देश के साथ संबंधों पर निर्भर रहने के बजाय कई स्तरों पर साझेदारियां मजबूत कर रहा है। वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय सहयोग का दायरा भी बढ़ाना चाहता है।

बहरहाल, पाकिस्तान को एफ-16 सहायता पर अमेरिकी मंत्री के सामने दोटूक आपत्ति और जापान-ऑस्ट्रेलिया के साथ 'JAI' का संदेश, ये दोनों घटनाक्रम मिलकर भारत की उस रक्षा नीति को रेखांकित करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर दृढ़ता और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का विस्तार साथ-साथ चलते हैं। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत की रक्षा कूटनीति का यही व्यापक दृष्टिकोण उसे बदलते वैश्विक परिदृश्य में अधिक सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर देता है।

आज का इतिहास

1755 पुर्तग़ाल की राजधानी लिस्बन में भूकंप से 50 हजार से अधिक लोगों की मौत।
1765 ब्रिटेन के उपनिवेशों में स्टैम्प एक्ट लागू किया गया।
1800 जॉन एडम्स व्हाइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने।
1858 भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासक के पास चला गया तथा गवर्नर-जनरल की जगह अब वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी।
1881 कलकत्ता में ट्राम सेवा स्यालदाह तथा अर्मेनिया घाट के बीच शुरू हुई।
1913 स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की शुरुआत की।
1922 ओटोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया। उसके सुल्तान महमूद छह को बहिष्कृत कर दिया गया।
1944 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की सेना नीदरलैंड के वालचेरेन पहुंची।
1946 पश्चिम जर्मनी के राज्य निदरसचसेन का गठन किया गया।
1950 भारत में पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया।
1952 जय नारायण ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया।
1954 फ्राँसीसी क्षेत्र पांडिचेरी, करिकल, माहे तथा यानोन भारत सरकार को सौंपे गये।
1956 कर्नाटक राज्य की स्थापना।
1956 भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया।
1958 तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया।
1966 हरियाणा राज्य की स्थापना।
1973 मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया।
1974 संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी भूमध्यसागरीय देश सायप्रस की स्वतंत्रता को मान्यता दी।
1979 बोलिविया में सत्ता पर सेना का कब्ज़ा।
1995 अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा पाकिस्तान को 36.80 करोड़ डॉलर के हथियार देने संबंधी बहुचर्चित %ब्राउन संशोधन% पारित।
1995 नरेन्द्र कोहली ने पचपन वर्ष की अवस्था में स्वैच्छिक अवकाश लेकर नौकरियों का सिलसिला समाप्त कर दिया।
1998 ढाका में दक्षिण अफ़्रीका ने वेस्टवंडीज को हराकर क्रिकेट का विल्स मिनी विश्व कप जीता।
2000 यूगोस्लाविया को आठ वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता हेतु सुरक्षा परिषद द्वारा मंजूरी।

एमएलसी चुनाव : नागपुर ने ही रखी कांग्रेस की लाज!

अजय बोकिल

देश के चार राज्यों की विधान परिषद (लेजिस्लेटिव कौंसिल) की 28 सीटों के नतीजे यूं तो समूचे देश के राजनीतिक मूड को प्रतिबिम्बित नहीं करते, लेकिन धारणा और सियासी रणनीति के स्तर पर इनका महत्व जरूर है। खास बात यह है कि इन चुनावों में मतदाताओं ने बड़ी पार्टियों को तगड़ा झटका दिया है। ये पार्टियां अपनी हार से ज्यादा इस बात से खुश है कि प्रतिद्वंदवी पार्टी भी हार गई। जबकि यूपी में सपा और महाराष्ट्र में कांग्रेसनीत महाविकास आघाडी ने बेहतर प्रदर्शन किया।

भाजपा नागपुर स्नातक सीट से हारी तो इसी नागपुर ने कांग्रेस की लाज रख ली। वरना पार्टी ने कांग्रेस शासित कर्नाटक में अपनी इकलौती सीट भी गवां दी थी। देश में एसआईआर और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी कांग्रेस को केवल इसी सीट पर जीत मिली। जबकि ये चुनाव कांग्रेस की पुरानी मांग कि चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हों, के जरिए हुए थे।

नागपुर सीट जीतने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर यह कहकर हमलावर है कि वह अपने सभी कोर नगरों जैसे कि वाराणसी, मथुरा और अयोध्या में चुनाव हार चुकी है। सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर में भी जैसे-तैसे जीती। नागपुर में बीजेपी की हार इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह सीएम देवेन्द्र फडणवीस का गृह क्षेत्र और भाजपा की मातृसंस्था आरएसएस का मुख्यालय है।

हालांकि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज किया कि वह ईवीएम से तो चुनाव हार ही रही थी, अब बैलेट पेपर में भी उसने मुंह की खाई है। इस तंज का साफ आशय यह था कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की बजाए कांग्रेस पहले अपना घर ठीक करे और चुनाव प्रबंधन को मजबूत करे। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस की दयनीय जीत जहां उत्तर प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनावों में सपा के साथ सीट बंटवारे में सौदेबाजी की उसकी ताकत को कमजोर करेगी, वहीं 1 नवंबर को दिल्ली में सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर आयोजित विपक्षी मार्च में पार्टी के तेवरों को ढीला कर सकती है।



समग्रता में इन नतीजों को देखें तो कुल 28 सीटों में से 16 सीटें तीन राज्यों में सत्तारूढ़ एनडीए ने जीतीं जबकि इंडिया ब्लॉक और निर्दलीयों ने बाकी की 12 सीटें जीतीं। इनमें सबसे अहम मुकाबला यूपी में था। वहां की 11 सीटों में से भाजपा ने 6 और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीत लीं। यहां सपा को पहले के मुकाबले 2 सीटों का फायदा हुआ।

जबकि भाजपा कुल सीटें तो पहले जितनी जीतने में कामयाब रही, लेकिन वह प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव हार गई। इन चुनाव नतीजों का आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ आकलन किया जाए तो मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए तीसरी बार सत्ता में लौटने की राह बहुत आसान नहीं रहने वाली है।

यूपी के अलावा बाकी तीन राज्यों में एमएलसी चुनाव नतीजों का प्रतीकात्मक महत्व ज्यादा है, क्योंकि वहां तत्काल कोई बड़ा चुनाव नहीं है। दूसरा दिलचस्प नतीजा महाराष्ट्र का है, जहां कुल पांच विधान परिषद सीटों पर चुनाव हुए। इनमें भाजपा ने कांग्रेस से एक सीट छीन ली। लेकिन जो नागपुर स्नातक सीट उसके पास थी, वो कांग्रेस के हाथों गवां दी। इसी तरह शरद पवार की एनसीपी ने भी दो सीट जीत लीं। एक शिवसेना को मिली।

बिहार में यूं तो सत्तारूढ़ एनडीए इस चुनाव में भी भारी पड़ा। वहां बीजेपी ने 3 सीटें जीतकर 1 सीट की वृद्धि की, वहीं उसकी सहयोगी जेडीयू ने प्रतिष्ठापूर्ण पटना सीट जीत ली। यानी कुल 8 में 4 एनडीए के खाते में गईं, जबकि एक जनसुराज पार्टी, 1 आरजेडी और दो निर्दलीयों को मिली। जीतने वाला एक ये निर्दलीय भी भाजपा का ही बागी है। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका उसके द्वारा शासित कर्नाटक में लगा, जहां विधान परिषद में उसकी इकलौती सीट भी भाजपा की सहयोगी जेडीएस ने छीन ली। जबकि भाजपा ने अपनी 3 सीटें बरकरार रखीं। ये सभी चुनाव मत पत्र (बैलेट पेपर) से हुए। जिसमें कांग्रेस अपनी पूर्व की 3 में से केवल 1 सीट बचा पाई। दूसरी तरफ इन एमएलसी चुनावों में भाजपा ने अपनी पहले की 11 सीटों में 2 का और इजाफा करते हुए 13 सीटें जीतीं। इसी तरह यूपी में सपा ने भी दो सीटें ज्यादा हासिल कीं। महाराष्ट्र में एनसीपी (शरद) ने भी अपनी एक सीट बढ़ाई है। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी पार्टियों को भी कोई न कोई सीट मिली है। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को दो सीटों पर ही संतोष करना पड़ा।

वैसे कांग्रेस कर्नाटक में अपनी हार से चिंतित होने के बजाए नागपुर स्नातक सीट जीतकर ज्यादा खुश है। उसका मानना है कि यह भाजपा के मर्मस्थल पर उसकी जीत का ठप्पा है। वैसे विधान परिषद के चुनाव आम चुनावों से काफी अलग होते हैं। इनके निर्वाचन क्षेत्र भी और मतदाता सूचियां भी अलग होती हैं। ऐसे में इन नतीजों को पब्लिक मूड से जोड़ना सही नहीं होगा। मसलन कर्नाटक में अपनी एक मात्र सीट गंवाने के बाद वहां के मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र प्रियांक खरगे ने कहा कि नतीजे जनमत परिचायक नहीं है। हम 2028 के विधानसभा चुनाव में फिर वापसी करेंगे। राज्य के सीएम डी. शिवकुमार ने कहा कि हम नतीजों की समीक्षा करेंगे। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इस हार के बाद भी कांग्रेस चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग पर कायम रहेगी। वैसे कर्नाटक कांग्रेस में भीतरी घमासान जारी है। यह परिणाम भी उसीकी बानगी है। हालांकि वहां अंदरूनी कलह भाजपा में भी है, लेकिन लगता है कि इन चुनावों में उसे काफी हद तक मैनेज कर लिया गया।

एक अहम प्रश्न बैलेट पेपर से चुनाव कराने का है। चूंकि इसमें धांधलियों की गुंजाइश ज्यादा है, इसलिए तीन स्थानों पर गड़बड़ियां हुईं। फिर से मतदान कराना पड़ा। मतगणना और नतीजा घोषित करने में दो दिन का समय लगा। मतगणना की चरणवार घोषणा धीमी होने पर सपा नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा की हार छुपाने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहा है। लेकिन यही आरोप तब भी लगाया जा सकता था, यदि चुनाव आयोग तेजी से मतगणना कराकर नतीजे घोषित कर देता। तब कहा जाता कि भाजपा को जिताने के लिए आयोग ऐसा कर रहा है। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी।

समग्रता में देखें तो आज मोबाइल और एआई के जमाने में बैलेट पेपर से चुनाव कराना 'हवाई जहाज के रहते बैलगाड़ी से बंबई जाने' जैसा है। अब मतदाताओंको भी आराम से उठने वाली पंगतों में खाने की आदत नहीं रही, बुफे का जमाना है।

यही चुनाव अगर ईवीएम से होता तो उसी दिन शाम तक नतीजों की तस्वीर साफ हो जाती। चुनाव हारने वाली पार्टियों को छोड़ दें तो शायद ही कोई चाहेगा कि अब चुनाव तीन दशक पहले की तरह बैलेट पेपर से हों और नतीजे जानने का मानसिक दबाव चार-चार दिनों तक बना रहे। वैसे विदेशों में अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, जैसे कि इजराइल जैसे छोटे से देश के आम चुनाव नतीजे आने में पूरे दो दिन लग गए। लेकिन इससे नतीजे तो नहीं बदले। यूं भी जिस क्षेत्र में हम दुनिया में आगे हैं, वहां उलटी चाल चलने का क्या मतलब है?

यहां एक बड़ा सवाल राज्यों में विधान परिषदों की उपयोगिता का है। देश के कुल 29 में से केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषदें हैं। इनमें ज्यादातर बड़े राज्य ही हैं। लेकिन तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं और इनके न होने से कोई काम रूकता नहीं है। यह सही है कि केन्द्र में राज्य सभा की तर्ज पर राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान संविधान की धारा 169/171 में है।

इसका मकसद यही था कि उच्च सदन के रूप में ये परिषदे सीधे निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के काम पर नियंत्रण रखें। लेकिन कालांतर में विधान परिषदें केवल चुनाव लड़ने से बचने वाले या फिर हारे हुए नेताओं के सुरक्षित पुनर्वास की जगह बन गईं।

कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री तो विधान परिषद के सदस्य बनकर ही अपना कार्यकाल गुजार देते हैं। अब विधान परिषद का व्यावहारिक अर्थ केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के तहत अपने आदमियों को एमएलसी बनाकर 6 साल के उपकृत करना भर रह गया है। चूंकि ये सदस्य सीधे जनता से निर्वाचित नहीं होते, इसलिए उनकी जनता के प्रति कोई खास जवाबदेही नहीं होती। जबकि विधान परिषद और उसके सदस्यों के खर्च का बोझ राज्य सरकार और प्रकारांतर से जनता पर ही पड़ता है। इसलिए इन चुनाव नतीजों के विश्लेषण से ज्यादा बहस तो इस बात पर होनी चाहिए कि विधान परिषदों को बनाए रखने का क्या औचित्य है?

राहुल का 'दिल्ली मार्च' में शामिल होने का आह्वान

राहिल नोरा चोपड़ा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के इच्छुक लोगों से 1 नवम्बर को 'चलो दिल्ली रामलीला मार्च' में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र को बचाने, वोटों की चोरी रोकने और संविधान की रक्षा करने का एक आंदोलन बताया। 'एक्स' पर एक वीडियो में, राहुल गांधी ने कहा कि यह देश के लिए एक अनूठा विरोध प्रदर्शन है। राहुल ने कहा, ''चलो दिल्ली' रामलीला मार्च लोकतंत्र को बचाने, वोटों की चोरी पर रोक लगाने और संविधान की रक्षा करने का मार्च है।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि यह किसी एक राजनीतिक दल का मार्च नहीं, यह भारत की मूल आत्मा के लिए एक मार्च है। उन्होंने राजनीतिक संबद्धता से परे सभी छात्र समूहों से भी विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया। इंडिया गठबंधन के दल 1 नवम्बर की रैली के लिए 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने की योजना बना रहे हैं, जिससे उन्हें ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार पर दबाव बढने की उम्मीद है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि रामलीला मैदान की रैली में कितनी भीड़ जुटती है।

सपा का चुनाव प्रबंधन : उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों के हालिया परिणामों ने समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों और चुनाव प्रबंधन को रेखांकित किया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सीटों के चुनावों में भाजपा ने कुल 6 सीटें जीतीं, जबकि समाजवादी पार्टी ने पांच। भाजपा को वाराणसी, लखनऊ, झांसी और आगरा क्षेत्र के अपने गढ़ों में झटका लगा है। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी शिक्षक एम.एल.सी. सीट और वाराणसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दोनों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। सपा ने लखनऊ स्नातक, इलाहाबाद-झांसी स्नातक और आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र भी जीते। इस बीच, भाजपा ने अपनी अधिकांश प्रमुख सीटें बरकरार रखीं, वहीं सपा ने अपनी संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी, जिससे पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को इन परिणामों को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पार्टी की बढ़ती चुनौती के संकेत के रूप में रेखांकित करने का अवसर मिल गया।

आजम खान को लेकर तकरार : साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मुहाने पर खड़े होने के साथ ही, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की रामपुर जिला जेल में पार्टी नेता आजम खान से मुलाकात की, जिससे भाजपा के साथ राजनीतिक टकराव शुरू हो गया। दूसरी ओर, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने पर खान को राज्य का गृह मंत्री बनाने की योजना बना रही है। तावड़े ने खान पर अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और दावा किया कि ऐसी स्थिति राज्य के विकास को पटरी से उतार देगी। वहीं, अखिलेश ने भाजपा सरकार पर खान और उनके परिवार के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं।

टाटा ग्रुप पर राजनीति करते ही फँस गये राहुल गांधी

नीरज कुमार दुबे

टाटा समूह के नेतृत्व से जुड़े विवाद पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बीच अब एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन का बयान भी चर्चा में है। हम आपको याद दिला दें कि शिवशंकरन ने पूर्ववर्ती यूपीए शासनकाल के दौरान कारोबारियों पर कथित राजनीतिक दबाव का अपना अनुभव साझा किया था। उन्होंने कहा था कि उस समय कारोबार बढ़ने पर उद्यमियों को अपनी कंपनी किसी खास व्यक्ति को बेचने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता था, जबकि आज कारोबारी माहौल पहले से अलग है। उनके बयान ने कांग्रेस शासनकाल में उद्योग जगत और राजनीतिक सत्ता के संबंधों पर बहस को एक नया संदर्भ दिया है।

हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर आरोप लगाया कि टाटा को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और देश के बड़े कारोबारी नेता इस मुद्दे पर बोलने से डर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि कारोबारी कब तक चुप रहेंगे और क्या भारतीय कारोबार सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की जागीर है। दरअसल, यह विवाद टाटा संस के चेयरमैन



एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को लेकर टाटा ट्रस्ट्स की ओर से उठाई गई आपत्तियों के बीच सामने आया था। राहुल गांधी ने इस आंतरिक कॉरपोरेट विवाद को सरकार और कारोबारी जगत के संबंधों से जोड़ते हुए राजनीतिक मुद्दा बनाया।

राहुल गांधी के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। उन्होंने व्यावसायिक और कानूनी मामलों को बिना ठोस आधार के आपराधिक करार देने पर भी आपत्ति जताई। सीतारमण ने कांग्रेस के शासनकाल के लाइसेंस-कोटा राज का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि उस व्यवस्था ने भारतीय उद्यमियों की कारोबारी क्षमता और उद्यमशीलता को बाधित किया। इसके विपरीत उन्होंने केंद्र की मौजूदा सरकार की नीतियों को उद्योग, निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने वाला बताया।

इसके बाद, राहुल गांधी ने जवाब में सवाल किया कि टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के प्रतिनिधियों को अमित शाह के आवास पर किस कारोबारी या कानूनी मामले के सिलसिले में बुलाया गया था। इस तरह दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो गए।

दूसरी ओर, आपको याद दिला दें कि एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन ने मई 2024 में उद्यमी और पॉडकास्ट होस्ट राज शमानी के कार्यक्रम में अपने कारोबारी अनुभव साझा किए थे। शिवशंकरन ने कहा था कि पहले भारत में कारोबार बढ़ने पर उद्यमियों को कंपनी किसी खास व्यक्ति को बेचने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता था। एयरसेल में अपनी 74 प्रतिशत हिस्सेदारी की 2006 में मैक्सिस को हुई बिक्री का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें इस सौदे से लगभग 3,400 करोड़ रुपये मिले, जबकि उनके मुताबिक एटीएंडटी को बेचने पर उन्हें आठ अरब डॉलर तक मिल सकते थे। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें सबसे ऊंची पेशकश स्वीकार करने का अवसर नहीं मिला।

शिवशंकरन ने तत्कालीन कारोबारी माहौल और मौजूदा स्थिति की तुलना करते हुए कहा था, "Today no one can pressurize you", साथ ही उन्होंने भारत को अब उदारीकृत अर्थव्यवस्था बताया था। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा था कि पहले कारोबारियों को किसी खास खरीदार को कंपनी बेचने के लिए दबाव झेलना पड़ता था, जबकि अब उद्यमी अपना कारोबार बनाने और आगे बढ़ाने के लिए अधिक स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं।

हम आपको बता दें कि एयरसेल की बिक्री को लेकर शिवशंकरन ने पहले भी आरोप लगाए थे कि उन पर कंपनी को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचने का दबाव बनाया गया। तत्कालीन दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन से जुड़े आरोपों की जांच हुई थी। हालांकि, 2017 में विशेष सीबीआई अदालत ने मारन बंधुओं को मामले में आरोपमुक्त कर दिया था।

बहरहाल, राहुल गांधी का आरोप है कि कारोबारी नेता मौजूदा सरकार के दबाव में खुलकर बोलने से बच रहे हैं। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के शासनकाल की लाइसेंस-कोटा व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं, एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन का बयान इस बहस को एक अलग संदर्भ देता है। उन्होंने अपने कारोबारी अनुभव साझा करते हुए बताया था कि पहले उद्यमियों पर अपनी कंपनी किसी खास खरीदार को बेचने का दबाव बनाया जाता था। उन्होंने मौजूदा कारोबारी माहौल को पहले से अलग बताया। खैर...अब सारा प्रकरण जनता के सामने है और चुनावों के दौरान जनता की अदालत में ही फैसला होगा कि कौन सही है और कौन गलत।

विपक्ष विकास के बजाय चुनाव आयोग को बना रहा निशाना

कातिलाल मांडोत

कांग्रेस की राजनीति इन दिनों एक बार फिर सत्ता हासिल करने की बेचैनी और खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिशों के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने, जनसमस्याओं को उठाने और जनता के हितों की रक्षा करने की होती है, लेकिन जब विपक्ष का अधिकांश राजनीतिक समय सरकार को घेरने, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने और आंदोलनों के माध्यम से राजनीतिक माहौल बनाने में व्यतीत होने लगे तो उसकी मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कांग्रेस की अगुआई में इंडिया गठबंधन जिस तरह विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के विरुद्ध अभियान चला रहा है, उससे यही प्रतीत होता है कि विपक्ष ने जनता के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के बजाय टकराव की राजनीति को प्राथमिकता दे रखी है।

उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एसआईआर के मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल बनाने में जुटे हैं। विपक्ष को उम्मीद है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर उठाए जा रहे सवालों के माध्यम से वह जनता के बीच अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर सकेगा। इसी रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन ने 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध संसद के मॉक सत्र और प्रतीकात्मक महाभियोग जैसी कार्यवाही आयोजित करने की तैयारी की। इस आयोजन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका महत्वपूर्ण रखी गई और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को मॉक संसद की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद एक नवंबर को दिल्ली के



रामलीला मैदान में बड़ी रैली और दिल्ली चलो मार्च का आयोजन प्रस्तावित है। कांग्रेस ने इस रैली में दस लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई है, जबकि दिल्ली पुलिस का अनुमान इससे काफी कम है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस इस अभियान को केवल चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अवसर मान रही है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का यह बयान भी उसकी आक्रामक रणनीति को दर्शाता है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया नहीं जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। विपक्ष के लिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, लेकिन किसी संवैधानिक संस्था के प्रमुख को राजनीतिक मंचों पर कठघरे में खड़ा करने और हटाने की मांग को लगातार आंदोलन का केंद्र बनाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिहाज से भी गंभीर बहस का विषय है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का अधिकार विपक्ष को है, लेकिन उन सवालों के समर्थन में ठोस तथ्य और संवैधानिक प्रक्रिया भी उतनी ही आवश्यक है। केवल राजनीतिक आरोपों और नारों से किसी संस्था की विश्वसनीयता निर्धारित नहीं की जा सकती।

कांग्रेस की रणनीति पर सबसे बड़ा सवाल कर्नाटक से उठता है, जहां उसी की सरकार सत्ता में है। कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली ने एसआईआर प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में यह कार्य सही तरीके से किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका विरोध एसआईआर से नहीं, बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसे लागू करने के तरीके से था। कर्नाटक में लगभग एक करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के संबंध में उन्होंने बताया कि इनमें मृत मतदाता, दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके लोग और मतदाता सूची में एक से अधिक बार दर्ज नाम शामिल थे। उनके अनुसार राज्य में उचित प्रशिक्षण और विरोध के बीच भी प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से पूरी हुई।

यही वह विरोधाभास है जो कांग्रेस की राजनीति को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। यदि मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया कर्नाटक में उचित है तो दूसरे राज्यों में भी उसके सिद्धांतों और उद्देश्यों पर समान दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि कहीं प्रक्रिया में वास्तविक गड़बड़ी है तो उसकी जांच और सुधार की मांग होनी चाहिए, लेकिन एक ही प्रक्रिया को अपनी सरकार वाले राज्य में सही और दूसरे राज्यों में राजनीतिक संघर्ष का विषय बनाना दोहरे मापदंड की आशंका पैदा करता है। लोकतंत्र में सिद्धांत सुविधानुसार नहीं बदले जा सकते। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना होगा कि उसका विरोध एसआईआर की प्रक्रिया से है या उन राज्यों में उसके राजनीतिक प्रभाव की आशंका से जहां उसकी सत्ता नहीं है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी जंतर-मंतर पर युवाओं के आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस युवाओं को आगे करके अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। कांग्रेस इस आरोप को राजनीतिक बयानबाजी कह सकती है, लेकिन यह भी विचारणीय है कि युवाओं के वास्तविक मुद्दों को राजनीतिक दल अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने लगें तो उनके आंदोलन का मूल उद्देश्य पीछे छूट जाता है। युवाओं को रोजगार, शिक्षा, पारदर्शी भर्ती, बेहतर अवसर और सुरक्षित भविष्य चाहिए। उनकी आवाज को राजनीतिक दलों के शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनाने के बजाय समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव परिणाम भी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। भाजपा को छह और समाजवादी पार्टी को पांच सीटों पर जीत मिली। वाराणसी की दोनों सीटों पर सपा की जीत और लखनऊ स्नातक सीट पर भाजपा को मिली पराजय ने विपक्ष को उत्साहित होने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा की हार निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टि से चर्चा का विषय है। लेकिन कुछ चुनावी परिणामों को पूरे प्रदेश के जनादेश का संकेत मान लेना भी जल्दबाजी होगी। विधानसभा चुनाव में जनता स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार, विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और भविष्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर अपना निर्णय करती है।

कांग्रेस को यह समझना होगा कि राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए केवल विरोध प्रदर्शन, धरना, मार्च और सरकार पर आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है। जनता किसी दल को केवल इसलिए सत्ता नहीं सौंपती कि वह वर्तमान सरकार के विरुद्ध कितनी आक्रामक आवाज उठा रहा है। जनता यह भी देखती है कि उसके पास देश और प्रदेश के विकास का क्या दृष्टिकोण है, युवाओं के भविष्य के लिए क्या योजना है, किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे तथा आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य से बाहर निकालकर जनसेवा के वास्तविक धरातल पर लाए।

विधान परिषद- छोटा चुनाव बड़े सबक

मृत्युंजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 28 विधान परिषद सीटों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सर्वाधिक 11 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आ चुका है जो भाजपा तथा सपा के बीच 6-5 के परिणाम से समाप्त हुआ। यह था तो छोटा चुनाव किंतु इस पर सभी राजनैतिक विश्लेषकों की दृष्टि थी कि 2027 विधानसभा चुनाव के पहले कौन क्लीन स्वीप करता है किंतु शिक्षकों व स्नातकों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आगामी चुनाव किसी भी दल या गठबंधन के लिए बहुत आसान नहीं होंगे। मुकाबला कांटे का होगा। जिस दल के प्रत्याशी व कार्यकर्ता धरातल पर उतर कर अपने मतदाताओं के साथ गहन संपर्क व संवाद में रहेंगे उन्हीं को लाभ होगा। विधान परिषद चुनावों में भाजपा मात्र छह सीटों पर पर अपनी साख बचाने में सफल रही जबकि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के बल पर पांच सीटें जीतने में सफल रही और यही नहीं उसने वाराणसी, आगरा व लखनऊ में बीजेपी के गढ़ों में परचम फहराकर भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दीं। अब सपा में उत्साह का वातावरण है। उसके नेता व प्रवक्ता कह रहे हैं कि वर्ष 2024 में अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ और अब 2026 में काशी की नगरी में महादेव और लखनऊ में प्रभु श्रीराम के अनुज लक्ष्मणजी का भी आशीर्वाद मिल चुका है। सफलता से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत सतर्क हो जाने का समय आ गया है। यदि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के मतदाताओं ने जो रवैया दिखाया था और सपा -कांग्रेस गठबंधन ने प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जीत ली थीं अगर वही रुख अभी भी बरकार है तब यह परिस्थितियों को और भी कठिन बना सकता है।

भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ की स्नातक सीट पर लगा है। यहाँ पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश सिंह को सपा प्रत्याशी कांति सिंह ने बहुत आसानी से पराजित कर दिया। यह स्पष्ट संकेत है कि अगर भाजपा ने अपना चुनावी प्रबंधन और कार्यकर्ताओं व मतदाताओं के मध्य अपना संवाद, संपर्क, व्यवहार नहीं सुधारा तो फिरऔर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाराणसी का परिणम भी स्थिति को गंभीर बना रहा है। प्रदेश के संगठन पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। वाराणसी का जनमानस प्रश्न कर रहा है कि जो उम्मीदवार पिछले चुनावों में पराजित हो चुका था, जनता के मध्य कभी नहीं रहता, केवल चुनावो के छह महीने पूर्व गणेश परिक्रमा करके पार्टी का टिकट कैसे लेकर आ जाता है? ऐसी परिस्थितियों में उन कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है जो धरातल पर उतरकर पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है उतनी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी फिर भी वहां भाजपा के वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट और विधान परिषद की दोनों सीटों पर हार भाजपा के लिए चिंता का विषय है। काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य कारिडोर बना, जिससे पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, रोप-वे बन रहा है, वाराणसी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिलने जा रहा है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर क्रियाशील है, काशी को सांस्कृतिक-आध्यात्मिक गतिविधियों पूरे भारत से से जोड़ा जा रहा है, निवेशक आ रहे हैं, काशी - तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। इस सबके बाद भी वाराणसी में एमएलसी चुनावों में दोनों सीटों पर पराजय स्थानीय नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है। वाराणसी की पराजय से यह बात भी उठ रही है कि वाराणसी नगर भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा के लिए अच्छी बात ये है कि विधानसभा चुनावों के पूर्व एक लिटमस टेस्ट हो गया। अभी भी भाजपा के पास कार्यकर्ताओं में उत्साह जागरण तथा अपनी रणनीति नए सिरे से गढ़ने के लिए पर्याप्त समय है। प्रदेश भाजपा की नवगठित कर्यकारिणी की बैठक होने जा रही है जिसमें हर बिंदु पर चर्चा होगी। यहाँ अमित शाह जी की अध्यक्षता में कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। दीपावली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां तथा भाजपा का चुनाव अभियान प्रारंभ होगा। भाजपा के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जनमानस तो योगी-योगी कर रहा है किंतु कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। भाजपा के लिए अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने का समय है क्योंकि विभिन्न कारणों से उणमें धरातल पर उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है।

सर्दियों में आपकी सेहत



इन सर्दियों में यदि आप अपनी सेहत बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले पेट साफ करने की जरूरत है। पेट में कब्ज रहेगा तो कितने ही पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें, लाभ नहीं होगा। भोजन समय पर तथा चबा-चबाकर खाना चाहिए, ताकि पाचन शक्ति ठीक बनी रहे, फिर पौष्टिक आहार या औषधि का सेवन करना चाहिए। आचार्य चरक ने कहा है कि पुरुष के शरीर में वीर्य तथा स्त्री के शरीर में ओज होना चाहिए, तभी चेहरे पर चमक व कांति नजर आती है और शरीर पुष्ट दिखता है। हम यहाँ कुछ ऐसे पौष्टिक पदार्थों की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक के लोग सेवन कर लाभ उठा सकते हैं और बलवान बन सकते हैं-

- सोते समय एक गिलास मीठे गुनगुने गर्म दूध में एक चम्मच शुद्ध घी डालकर पीना चाहिए।
- दूध की मलाई तथा पिसी मिश्री जरूरत के अनुसार मिलाकर खाना चाहिए, यह अत्यंत शक्तिवर्द्धक है।
- एक बादाम को पत्थर पर घिसकर दूध में मिलाकर पीना चाहिए, इससे अपार बल मिलता है। बादाम को घिसकर ही उपयोग में लें।
- छाछ से निकाला गया ताजा माखन तथा मिश्री मिलाकर खाना चाहिए, ऊपर से पानी बिलकुल न पिएँ।
- 50 ग्राम उड़द की दाल आधा लीटर दूध में पकाकर खीर बनाकर खाने से अपार बल प्राप्त होता है। यह खीर पूरे शरीर को पुष्ट करती है।
- प्रात- एक पाव दूध तथा दो-तीन केले साथ में खाने से बल मिलता है, कांति बढ़ती है।



- एक चम्मच असगंध चूर्ण तथा एक चम्मच मिश्री मिलाकर गुनगुने एक पाव दूर के साथ प्रात- व रात को सेवन करें, रात को सेवन के बाद कुल्ला कर सो जाएँ। 40 दिन में परिवर्तन नजर आने लगेगा।
- सफेद मूसली या धोली मूसली का पावडर, जो स्वयं कूटकर बनाया हो, एक चम्मच तथा पिसी मिश्री एक चम्मच लेकर सुबह व रात को सोने से पहले गुनगुने एक पाव दूध के साथ लें। यह अत्यंत शक्तिवर्धक है।
- सुबह-शाम भोजन के बाद सेवफल, अनार, केले या जो भी मौसमी फल हों, खाएँ।
- सुबह एक पाव ठंडे दूध में एक बड़ा चम्मच शहद मिलाकर पीने से खून साफ होता है, शरीर में खून की वृद्धि होती है।
- प्याज का रस 2 चम्मच, शहद 1 चम्मच, घी चौथाई चम्मच मिलाकर सेवन करें और स्वयं शक्ति का चमत्कार देखें। यह नुस्खा यौन शक्ति बढ़ाने में अचूक है। ऊपर वर्णित नुस्खे स्त्री-पुरुष दोनों के लिए समान हैं। इन्हें अनुकूल मात्रा में उचित विधि से सुबह-रात को सेवन करना चाहिए।
- भोजन में घी, दूध, चावल, उड़द, नारियल, मलाई, मक्खन, शहद, मौसमी फल, हलवा, हरी साग-भाजी, टमाटर, गाजर, आँवला आदि का सेवन करना चाहिए।
- सर्दियों में बादाम का हलवा, दूध में पकाया हुआ छुहारा, मीठा अनार, प्याज का रस, नारियल की गिरी और दूध की खीर, उड़द दाल का लड्डू, गन्ना रस, सौंठ और काली मिर्च तथा मैथी का लड्डू बहुत फायदेमंद है। योग्य वैद्य की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, ताकि अपने शरीर के अनुकूल पथ्य-अपथ्य का चयन किया जा सके।
- चिकनाईयुक्त, मधुर, लवण और अम्ल रस वाले पदार्थ का सेवन करके अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। बासी, दुर्गंधयुक्त, अधिक चटपटे मसालेदार खानपान से बचना ही श्रेयस्कर है।
- ठीक समय पर, चबा-चबाकर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करना चाहिए। भोजन के पूर्व नीबू पानी और भोजन के पश्चात छाछ पीना लाभदायक होता है।
- इस ऋतु में रूखे, कटु-तिक्त-कषाय, अति शीतल और वात प्रधान भोज्य पदार्थ न खाएँ । अन्यथा जोड़ों के दर्द, गठिया और सायटिका से पीड़ित हो सकते हैं। इसी प्रकार अधिक खटाई से भी बचें, ताकि खाँसी-सर्दी, जुकाम, नजला आदि से बचाव हो सके। नीबू और ताजा दही वर्जित नहीं है।
- शीतऋतु में अधिक देर तक भूखे न रहें, क्योंकि जठराग्नि की प्रबलता के कारण यथासमय भोजन नहीं करने से यह अग्नि शरीर की धातुओं को जला डालती है, जिससे जीवन-शक्ति का क्षय होता है।
- सेहत बनाने के लिए प्रतिदिन स्नान भी जरूरी है। कुछ लोग ठंड के डर से कई दिन तक नहाते नहीं, यह उचित नहीं। पानी कुनकुना कर लेना चाहिए। अत्यधिक ठंडा और अधिक गर्म पानी नुकसान पहुँचाता है।
- मल-मूत्र विसर्जन में आलस्य नहीं करना चाहिए। रात को सिर ढँककर सोना भी उचित नहीं होता।

स्वस्थ रहने के आसान उपाय



सुबह जल्दी उठो और 4- 6 किलोमीटर रोज टहलो। संभव हो तो शाम को भी थोड़ा टहलो। टहलते समय नाक से लम्बी- लम्बी सांसें लो तथा यह भावना करो कि टहलने से 2. टहलते समय नाक से लम्बी- लम्बी सांसें लो तथा यह भावना करो कि टहलने से आप अपने स्वास्थ्य को संवार रहे हैं।

टहलने के अलावा, दौडऩा, साइकिल चलाना, घुड़सवारी, तैरना या कोई भी खेलकूद, व्यायाम के अच्छे उपाय हैं। स्त्रियां चक्की पीसना,,रस्सीकूदना, पानी भरना, झाड़ू- पोछा लगाना आदि घर के कामों में भी अच्छा व्यायाम कर सकती हैं। रोज थोड़े समय छोटे बच्चों के साथ खेलना, 10- 15 मिनट खुलकर हंसना भी अच्छे व्यायाम के अंग हैं।

प्रात- टहलने के बाद भूख अच्छी लगती है। इस समय पौष्टिक पदार्थों का सेवन करें। अंकुरित अन्न, भीगी मूंगफली, आंवला या इससे बना कोई पदार्थ, संतरा या मौसम्मी का रस अच्छे नाश्ता का अंग होते हैं। भोजन सादा करो एवं उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करो, शांत, प्रसन्न और निश्चिन्तता पूर्वक करो और उसे अच्छी तरह चबाचबा कर खाओ। खाते समय न बात करो और न हंसो। एकाग्र चित्त होकर भोजन करना चाहिए। भूख से कम खाओ अथवा आधा पेट खाओ, चौथाई पानी के लिए एवं चौथाई पेट हवा के लिए खाली छोड़ो।

भोजन में रोज अंकुरित अन्न अवश्य शामिल करो। अंकुरित अन्न में पौष्टिकता एवं खनिज लवण गुणात्मक मात्रा में बढ़ जाते हैं। इनमें मूंग सर्वोत्तम है। चना, अंकुरित या भीगी मूंगफली इसमें थोड़ी मेथी दाना एवं चुटकी भर- अजवायन मिला लें तो यह कई रोगों का प्रतिरोधक एवं प्रभावी ईलाज है।

मौसम की ताजा हरी सब्जी और ताजे फल खूब खाओ। जितना हो सके कच्चे खाओ अन्यथा आधी उबली/ उबली तथा कम मिर्च- मसाले, खटाई की सब्जियां खाओ। एक ग्रास रोटी के साथ चार ग्रास सब्जी के अनुपात का प्रयास रखो।

आटा चोकर समेत खाओ, सम्भव हो तो हाथ का पिसा हुआ खाओ। जौ, गेहूं, चना, सोयाबीन का मिस्सी रोटी का आटा सुपाच्य एवं पौष्टिक होता है। पौष्टिकता की दृष्टि से रोटी में हरी सब्जी, पालक, मेथी, बथुआ आदि पत्तीदार सब्जी मिलाकर बनायें / खायें। दलिया / खिचड़ी में भी पत्तीदार एवं हरी सब्जियाँ मिलाकर पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है। सब्जियों के सूप का नित्य सेवन पौष्टिक एवं हलके भोजन का अच्छा अंग हो सकता है। भोजन के साथ पानी कम से कम पियो। दोपहर के भोजन के घंटे भर बाद पानी पियें । भोजन यदि कड़ा और रूखा हो तो 2- 4 घूंट पानी अवश्य पियें।

प्रात- उठते ही खूब पानी पियो। दोपहर भोजन के थोड़ी देर बाद छाछ और रात को सोने के पहले उष्ण दूध अमृत समान है। दिन में कम से कम दो-तीन लीटर पानी अवश्य पियो। धूम्रपान, मादक पेय- पदार्थ (जरदा, गुटखा, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोकाकोला, पेप्सी इत्यादि एवं शराब आदि) सर्वथा छोड़ दो। चाय- कॉफी आदि के स्थान पर सादा ठंडा या गुनगुना पानी, नींबू पानी, छाछ, गाजर, पालक चुकन्दर, लौकी, टमाटर इत्यादि सब्जियों का एव मौसम्मी या संतरा, पपीता इत्यादि फलों के रस का उपयोग लाभकारी होता है। डाइबीटीज (शक्कर) के रोगी को शक्कर या उससे बने पदार्थों से पूर्ण परहेज करना चाहिए। फलों में अधिक मीठे फल का सेवन कम करें। फल के रस के बजाय फल खायें। मेथी दाना और करेला मधुमेह रोग की राम बाण दवा है। मैथी दाना रोज 18/24 घंटे पानी में, जहां तक संभव हो सके मिट्टी के बर्तन में भिगोयें। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के पहले या बाद में दानामेथी का पानी पी लें। दानामेथी अंकुरित कर सलाद में या नमक, नींबू लगाकर भी खा सकते हैं।

एरोबिक्स यानी डांस, फन, रिदम और हेल्थ



स्वस्थ और सुंदर दिखने के नुस्खे दादी मां के पिटारे से लेकर आधुनिक साजो-सामान में बिखरे पड़े हैं। प्रत्येक समय, काल में सुंदरता का पैमाना भी परि?वर्तित हुआ है। जहाँ प्राचीन समय में गहनों से लकदक, लहराती केश राशि से सुसज्जित, सजीली-लजीली सुंदरियों का वर्चस्व था तो आज टाईट जींसधारी, लंबी, दुबली, छरहरी काया सुंदरता के मानदंड में शामिल है। प्रत्येक स्त्री अपनी सुंदरता के प्रति सजग है। अधिक चुस्त-दुरुस्त रहने के लिए डाइटिंग, योग, व्यायाम या एरोबिक्स का सहारा लेती है। बढ़ते हुए वजन या थुलथुल शरीर से चिंताग्रस्त, सदैव उदास और थका हुआ महसूस करने वाली स्त्रियां तथा जो अपनी व्यस्तता के कारण व्यायाम नहीं कर पाती या बेडौल काया के कारण योग क्लास, हेल्थ क्लब जाने में संकोच करने वाली स्त्रियों के लिए एरोबिक्स वरदान साबित हुआ है। एरोबिक्स यानी संगीत की धुन पर किए जाने वाले व्यायाम। एरोबिक्स करने के लिए कोई विशेष साजो-सामान की जरूरत नहीं होती। बस पर्याप्त स्थान हो, इस हेतु आप कमरे से फर्नीचर हटाकर स्थान बना सकती है। पॉप, रॉक, जाज संगीत का कोई कैसेट या कर्णप्रिय धुन तथा तेज लय वाला कोई भी कैसेट लेकर उसी आधार पर नृत्य करें। कैसेट लेते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि व्यायाम के समय जिन अंगों को रिद?म पर थिरकन देना है उसके लिए सही रिद?म और संगीत उस कैसेट में अवश्य हो। इन धुनों पर जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, तैराकी, जैसी गति में थिरकन की जाती है। इस हेतु जेनफौंडा द्वारा तैयार किए गए लयात्मक योग व्यायाम की कैसेट बाजार में उपलब्ध है। भारतीय सिने अभिनेत्री रेखा ने भी एरोबिक्स पर एक ऑडियो कैसेट माइंड एंड बॉडी तैयार किया है। इसमें योग और व्यायाम को लेकर एरोबिक्स के लिए धुन तैयार की है। अनीता राज, शिल्पा शेट्टी ने भी वीडियो कैसेट तैयार किए हैं। एरोबिक्स व्यायाम अकेले भी किए जा सकते हैं और समूह के साथ भी। समूह के साथ करने का अलग ही मजा है। सप्ताह में तीन-चार बार या समय उपलब्ध होने पर प्रतिदिन भी व्यायाम किया जा सकता है। वैसे भी अपेक्षाकृत इसमें बहुत ही कम समय लगता है। लगभग दस से बीस मिनट लगते हैं।



एरोबिक्स करने वाले लोगों का कहना है कि वे इस अनूठे नृत्य व्यायाम से तन-मन की प्रसन्नता महसूस करते हैं और शरीर पर जमी अनावश्यक चर्बी गायब हो जाती है। इन्हें करने के लिए कोई शिक्षक हो यह आवश्यक नहीं। एरोबिक्स के बारे में संगीत के रसिक तथा उद्योगपति का मानना है कि इस व्यायाम से उनमें अधिक चुस्ती-फुर्ती आती है और वे अधिक हल्का महसूस करते हैं। संगीत की सुमधुर आवाज तनाव, चिंता दूर करने में सहायक है। एरोबिक्स निश्चय ही जीवन में अनोखा बदलाव लाता है। होटलों, हेल्थ क्लबों, ब्यूटी पार्लर्स, यहां तक की कई लोगों ने निजी कक्षाएँ भी खोल ली हैं, जहां 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक फीस वसूली जाती है। आप अपने स्टैंडर्ड के अनुसार इन कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं या घर में ही मुफ्त में इसका आनंद उठा सकते हैं।

लाभदायक है सर्दियों में सिंघाड़े का सेवन



सर्दियां शुरू होते ही बाजार में सिंघाड़े आसानी से प्राप्त हो जाते है और यह खाने में बहुत स्वादिष्ट होते है। सिंघाड़ा हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है इसमें पाएं जानें वाले पौष्टिक तत्व हमारी शरीर को तंदरूस्त रखने में मदद करते है। सिंघाड़े में वैसे तो विटामिन बी,फाइबर और भी कई पौष्टिक तत्त्व पाएं जाते है पर विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाए जाते है जो हमारी त्वचा को सुंदर बनाने में मदद करते है। हमारे शरीर को भी शक्ति प्रदान करता है।

- सिंघाड़े का सेवन करने से त्वचा में चमक तो आती ही है और त्वचा निखारने में भी मदद करता है।
- कच्चे सिंघाड़े का सेवन करने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है।
- सर्दियों में सिंघाड़े का सेवन करना काफी लाभदायक होता है ,सिंघाड़े खाने से त्वचा तो निखरती ही है और साथ ही खुश्की की समस्या भी दूर हो जाती है।
- सिंघाड़े का सेवन करने से त्वचा संबंधी सभी रोगों से छुटकारा मिलता है जैसे धूप की अल्ट्रावायलेट किरणों से भी त्वचा की रक्षा करता है।
- सिंघाड़े का सेवन करने से गले में होने वाली खराश से राहत मिलती है और खांसी से भी छुटकारा मिलता है।
- सिंघाड़े का सेवन करने से हमें कई रोगों से राहत मिलती है जैसे पीलिया के रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है।
- सिंघाड़े खाने से त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों से भी राहत मिलती है।

औषधीय गुणों से भरपूर अजवायन



- अजीर्ण की शिकायत होने पर अजवायन का तेल तथा अर्क शीघ्र लाभ देते हैं।
- उदर शूल होने पर भी अजवायन का अर्क या तेल दें।
- दांत दर्द करते हों तो अजवायन को धीरे-धीरे चबाएं। चबाते समय दबाव कम डालें। रस निगल जाएं।
- मुंह से दुर्गंध आती हो तो भी अजवायन चबाया करें।
- सर्दी का बुखार परेशान करता हो तो अजवायन को गुड़ के साथ खाया करें। 5-6 दिनों में पूर्ण ठीक हो जाएंगे।
- जिन्हें सूतिका बुखार हो जाए, वह अजवायन का सेवन करें।
- प्रसूता नारियों को अजवायन खिलाने पर उनकी भूख खुल जाती है। उनकी पाचन शक्ति में वृद्धि होने लगती है।
- वायु गोला की शिकायत होने पर अजवायन एक चम्मच, काला नमक चौथाई चम्मच, पीस-छानकर ताजा पानी से लें।
- बार-बार पेशाब की शिकायत होने पर अजवायन तथा तिल मिलाकर रोगी को खिलाएं।
- गुर्दे का दर्द हो तो गुड़, पिसी कच्ची अजवायन, दोनों एक समान मात्रा में लें। मात्रा एक चम्मच, दिन में 4 बार।
- शरीर में शक्ति संचार करने के लिए यह चूर्ण, दिन में 2 बार, आधा चम्मच एक समय, ताजा पानी से दें।
- फोड़ा-फुंसी की सूजन होने पर नींबू के रस में अजवायन पीसकर दिन में 2 बार लेप करें।

घर के कामकाज से कम होता है तनाव

अगर आप तनाव के दौर से गुजर रहे हैं तो घरेलू कामकाज कीजिए। महज 20 मिनट का घरेलू काम आपको राहत देगा। आपका तनाव भागेगा और मानसिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। ब्रिटेन के अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि सप्ताह में कम से कम एक बार घरेलू कामकाज जैसी शारीरिक गतिविधियों के जरिये तनाव को कम किया जा सकता है। इसमें साफ-सफाई, बाग-बगीचे की देखभाल, मकान का रखरखाव आदि भी शामिल हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के मार्क हेमर के नेतृत्व में एक अध्ययन किया गया। उन्होंने अपने अध्ययन में 20000 लोगों को शामिल किया और उनकी दिमागी हालत को जानने का प्रयास किया।

यूं तो नियमित कसरत को मानसिक स्वास्थ्य के लिए बढ़िया माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञ कभी इस बात पर राजी नहीं हो सके कि किस तरह की और कितनी कसरत करना चाहिए।



राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

NVS-03 के सफल प्रक्षेपण पर मोदी ने इसरो की सराहना की

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक बार फिर अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए एक नई उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने अपने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV-F18) के जरिए अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह NVS-03 को उसकी निर्धारित कक्षा (ऑर्बिट) में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इस शानदार सफलता के बाद देश भर से वैज्ञानिकों को बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो की पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के समर्पण और सूझबूझ से पूरा देश गौरवान्वित है। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर सुबह-सुबह किए गए एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को भारत के स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम 'NavIC' को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही, उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प को भी दोहराया।



हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए भरा पर्चा

भोपाल। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्यप्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद थे। पुरी (74) सुबह 11 बजे के कुछ देर बाद विधानसभा भवन पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई थी। भाजपा ने इस सीट से पुरी को मैदान में उतारा है, जो एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। मुरुगन ने इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनका राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक था। मध्यप्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा अदालत के एक आदेश के कारण चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे।



इंडिया गठबंधन के चलो दिल्ली प्रदर्शन में शामिल होंगे सतीशन

तिरुवनंतपुरम। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन रविवार को नयी दिल्ली में विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के 'चलो दिल्ली' प्रदर्शन में शामिल होंगे। सतीशन ने कहा कि इसका उद्देश्य लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना तथा मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं से जुड़ी चिंताओं को उठाना है। सतीशन ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वह रामलीला मैदान में लाखों नागरिकों के साथ लोकतंत्र, संविधान और मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए खड़े होंगे। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इस बात की दृढ़ घोषणा है कि जब लोकतंत्र खतरे में होगा, तब हम चुप नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से एक नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले 'चलो दिल्ली' प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हाल ही में लोगों से विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के एक नवंबर के 'चलो दिल्ली' मार्च में शामिल होने का आग्रह किया था।



पंजाब चुनाव : आप ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें धुरी से मुख्यमंत्री भगवंत मान और लुधियाना पश्चिम से जेल में बंद मंत्री संजीव अरोड़ा का नाम शामिल है। पार्टी ने अपनी पहली सूची में मौजूदा 37 विधायकों को भी फिर से टिकट दिया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान कोटकपुरा से चुनाव लड़ेंगे। अरोड़ा, जो फिलहाल जेल में हैं, उन्हें एक बार फिर लुधियाना पश्चिम से मैदान में उतारा गया है। उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम शामिल होना सबसे अहम बातों में से एक है। अरोड़ा को इस साल मई में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया था। इस घोषणा के साथ, आम आदमी पार्टी (आप) ने आगामी पंजाब चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने कई मौजूदा विधायकों को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है।



व्यापारियों ने राहुल गांधी से दिल्ली मार्च स्थगित करने की अपील की

नई दिल्ली। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली के व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने शनिवार को एक बार फिर राहुल गांधी से एक नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की रैली को स्थगित करने की अपील की। सीटीआई ने अपनी अपील में कहा, आप (राहुल गांधी) हमेशा बोलते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाता हूं, हमारी दुकानें भी ग्राहकों के साथ आपसी विश्वास, प्यार और मोहब्बत के आधार पर ही चलती हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि भारत के सबसे बड़े त्यौहार दिवाली के पीक सीजन में हमारी मोहब्बत की दुकानें और व्यापार रैली की भेंट ना चढ़ जाए। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा, ये पोस्टर राहुल के लिए आईना है। आप भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में हमारी 300 साल पुरानी मोहब्बत की दुकानें रैली के कारण बंद करवा रहे हैं। चांदनी चौक की परांठे वाली दुकान, खारी बावली के मसाले, सदर की चूड़ी-बिंदी, चांदनी चौक का लहंगा, दरियागंज का एसी, चावड़ी बाजार की सेनिटरी, करोल बाग की मशहूर कुल्फी, ये सब मोहब्बत की दुकानें ही तो हैं।

अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया सरदार पटेल की यादों को मिटाने का आरोप

गृहमंत्री बोले- सिर्फ 1218 दिनों में सरदार पटेल ने देश को किया एकजुट

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस (राष्ट्रीय एकता दिवस) के मौके पर उन्होंने देश के राजनीतिक एकीकरण और राष्ट्र निर्माण में पटेल के योगदान को याद किया।

नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता संभालने के बाद से सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश को एकजुट करने में पटेल की अहम भूमिका थी और इसी वजह से उन्हें एक अखंड भारत का निर्माता माना जाता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कई वर्षों तक भारत ने सरदार साहब को उनके योगदान के लिए वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे वास्तव में हकदार थे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सरदार साहब की स्मृतियों को मिटाने की कोशिश की है। हालांकि, सूरज की चमक को छिपाया नहीं जा सकता।

उन्होंने कहा, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराकर सरदार साहब की विरासत को पूरे देश के सामने मजबूती से स्थापित किया। यह विशाल प्रतिमा आसमान की ऊंचाइयों को छूती है।

शाह ने कहा, जब भारत आजाद



हुआ था, तब दुनिया के राजनीतिक विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत बिखर जाएगा। लेकिन आजादी के बाद के 1,218 दिनों में सरदार पटेल ने वह कर दिखाया, जिसे सभी असंभव मानते थे। यह ऐसा काम था, जिसे शायद नेताओं का एक समूह भी मिलकर पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता। सरदार पटेल ने सिर्फ 1,218 दिनों में एकजुट भारत का निर्माण किया। सरदार पटेल का परिकल्पित और निर्मित भारत आज दुनिया के सामने गर्व से खड़ा है।

देश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं को आकार देने में सरदार पटेल की भूमिका का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि उनका योगदान सिर्फ रियासतों के विलय तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने देश की क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई।

शाह ने कहा, हम सभी जानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हम सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। वह एक महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने न केवल देश का इतिहास बदला, बल्कि उसके भूगोल को भी आकार दिया। कई रियासतों को एकजुट करने के कठिन काम को पूरा करते हुए उन्होंने सभी को एक सूत्र में पिरोया। सरदार साहब आज हमारे सामने मौजूद अखंड भारत के नक्शे के निर्माता बने।

उन्होंने आगे कहा, उन्होंने सिर्फ भारत के भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण के प्रयासों को सफल नहीं बनाया, बल्कि इन सभी को एक साथ जोड़कर देश को एक एकजुट राष्ट्र का रूप दिया। इस अवसर पर अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत की कल्पना की है, उसका पहला चरण नशामुक्त भारत है। पीएम मोदी के कार्यकाल में कई निर्णायक काम हुए हैं, जिनमें धारा 370 हटाना, कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ना, देश से नक्सलवाद समाप्त करना, एक देश, एक कर प्रणाली लागू करना शामिल है। इसके साथ ही कई और बड़े काम हुए हैं।

अमित शाह ने कहा, देश में भाषाई, सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधता हमारी कमजोरी नहीं, हमारी मजबूती है। यही सरदार पटेल का संदेश था। सोमनाथ के मंदिर के निर्माण की कल्पना भी सरदार पटेल ने की थी। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत देश को विश्व की अंतरराष्ट्रीय तालिकाओं में प्रथम स्थान की दिशा में आगे ले जा रहा है।

इंडिया ब्लॉक की रैली से पहले घमासान

रिजिजू की कांग्रेस को चुनौती पूछा- 2014 में क्यों हारे?

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल, आगामी एक नवंबर यानी कल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक की दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित होनी है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को पांच सवालों के जरिए घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर पार्टी को इन सवालों का जवाब देने की चुनौती दी। रिजिजू ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, मतदाता सूची से नाम हटाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए।

रिजिजू ने पूछे पांच सवाल?

- रिजिजू ने पूछा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें कैसे मिलीं, जबकि उस समय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी।
- उन्होंने दूसरा सवाल उठाया कि जब 2024 में ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, तब कांग्रेस को लगातार तीसरी बार चुनाव में हार का सामना कैसे करना पड़ा?
- केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि क्या कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्रियों को 2014 से 2026 के बीच बनी सरकारों से इस्तीफा देना चाहिए और इसके लिए



माफी मांगनी चाहिए?

- उन्होंने मतदाता सूची को लेकर भी सवाल किया। रिजिजू ने पूछा कि क्या अवैध प्रवासियों, मृत लोगों, दूसरी जगह जा चुके मतदाताओं और एक से अधिक बार दर्ज नामों को मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए या नहीं?
- रिजिजू ने अपने पांचवें सवाल में पूछा कि क्या 1952-56, 1958-61, 1965-66, 1983-84, 1987-88, 1993, 1995 और 2002-2004 के दौरान कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अवैध थे?

उन्होंने आरोप लगाया कि एक परिवार की पार्टी बाहरी ताकतों के साथ मिलकर संविधान और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रही है।

एक नवंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की प्रस्तावित महारैली को लेकर दिल्ली के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे समेत सभी घटक दलों को पत्र लिखकर रैली को दीपावली के बाद कराने की मांग की है।

इंडिया गठबंधन की 'चलो दिल्ली' रैली आज



नईदिल्ली। दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अराधना मिश्रा मोना ने कहा कि यह देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि अब आम लोग भी इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह आयोजन सफल होगा। अराधना मिश्रा ने कहा कि इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार पूरी तरह खो दिया है।

रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि गठबंधन अपने फैसले केवल दिल्ली की जनता ही नहीं, बल्कि देश के सभी 140 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर लेगा। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पूरे देश के नागरिकों के हितों से जुड़ा है। इसी उद्देश्य से रामलीला मैदान में रैली आयोजित की जा रही है, ताकि नागरिकों के हितों, लोकतांत्रिक अधिकारों, मतदान के अधिकार और संविधान की रक्षा की जा सके। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि देश के हर कोने से लोग यहां जुटेंगे और अपनी आवाज उठाते हुए अपनी चिंताओं को सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से रामलीला मैदान साफ हो गया है, जिससे नगर निगम का काम भी कम हुआ है।

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली पर कहा, हम भीड़ जुटाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि भीड़ जुट रही है क्योंकि लोग स्वयं आ रहे हैं। हमने किसी पार्टी की ओर से कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया है। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था। शुक्र मनाइए कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं थे और पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने साथ शामिल किया था क्योंकि वे चाहते थे कि सभी को साथ लेकर चला जाए।

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने 1 नवंबर को निर्धारित इंडिया ब्लॉक की विरोध रैली की तैयारियों को लेकर कहा कि तेलंगाना के सांसद रविवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने रामलीला मैदान पहुंचे। उन्होंने तैयारियों पर संतोष जताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि रविवार का कार्यक्रम सफल रहेगा। मल्लू रवि ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ट्रेनों और कोचों की अनुमति नहीं दे रही है, इसके बावजूद तेलंगाना से लोग रैली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि 200 से अधिक बसें आ रही हैं और बड़ी संख्या में लोग नियमित ट्रेनों से भी यात्रा कर रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी टी20 मैच आज

हैमिल्टन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला रविवार, 1 नवंबर 2026 को खेला जाएगा। यह मुकाबला न्यूजीलैंड के हैमिल्टन स्थित सेडन पार्क में आयोजित होगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया ने शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली थी, लेकिन चौथे टी20 में न्यूजीलैंड ने 87 रनों से शानदार जीत दर्ज कर वापसी के संकेत दिए। अब भारतीय टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज का अंत दमदार अंदाज में करना चाहेगी।



ऑकलैंड में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 87 रनों से हराया था। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने सीरीज में लगातार तीन हार के बाद वापसी की। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स के तूफानी शतक की बदौलत 259/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में भारतीय टीम 172 रन ही बना सकी और मुकाबला गंवा दिया।

चौथे टी20 में भारतीय बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गई थी। शुरुआती विकेट गिरने के बाद टीम दबाव से बाहर नहीं निकल सकी और लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। ऐसे में भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाज आखिरी मुकाबले में अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे।

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी में ग्लेन फिलिप्स सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में शामिल हैं। चौथे टी20 में उन्होंने शानदार शतक लगाकर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। फिलिप्स ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और न्यूजीलैंड को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

खाद्य तेलों ने बिगाड़ा रसोई का बजट

नई दिल्ली। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। दशहरा, दीपावली और छठ को लेकर बाजारों में रौनक है और लोग तैयारियों में जुटे हैं लेकिन बढ़ती महंगाई ने त्योहारों की खुशियों पर असर डालना शुरू कर दिया है। खासतौर पर खाद्य तेलों की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सरकार की ओर से खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती किए जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को कीमतों में राहत नहीं मिली है। पिछले एक साल के दौरान खाने के तेल की कीमतों में करीब 15 से 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर में ही रिफाइंड तेल लगभग 15 फीसदी और मूंगफली का तेल करीब 14 फीसदी महंगा हुआ। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने सितंबर में आयात शुल्क में 5 फीसदी की कटौती की थी।

सन फार्मा का मुनाफा दूसरी तिमाही में 36 प्रतिशत घटा

नई दिल्ली। दवा कंपनी सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 36.36 प्रतिशत घटकर 1,988.53 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 3,124.95 करोड़ रुपए था। सन फार्मा ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2026-26 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में उसकी एकीकृत परिचालन आय बढ़कर 16,198.71 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 14,478.31 करोड़ रुपए थी। देश में दवाओं की बिक्री बढ़ने से आय में वृद्धि हुई। इस दौरान भारत में कंपनी की दवाओं की बिक्री 17.3 प्रतिशत बढ़कर 5,552.3 करोड़ रुपए हो गई। यह तिमाही में कंपनी की कुल एकीकृत बिक्री का 34.5 प्रतिशत थी।

2027 से बाजार में आ सकते हैं प्लास्टिक के नोट

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जल्द ही देश में प्लास्टिक करेंसी की शुरुआत की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरबीआई 1 अप्रैल 2027 से 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों का फील्ड ट्रायल शुरू कर सकता है। खास बात यह है कि इन नए नोटों का आकार मौजूदा कागज के नोटों जैसा ही रखने की योजना है। इससे बैंकों को एटीएम मशीनों में बदलाव कराने पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई की योजना नोटों की लंबाई और चौड़ाई पहले जैसी रखने की है। दरअसल, अगर नए नोटों का आकार बदलता है तो ज़रूरमें लगे सेंसर, नोट रखने वाले हिस्सों और अन्य तकनीकी सुविधाओं को अपडेट करना पड़ सकता है। इससे बैंकों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। नोटों का आकार पहले जैसा रखने से बैंकों को बड़ी बचत हो सकती है।

कपास के आयात की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली। सरकार ने घरेलू कपड़ा क्षेत्र में कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 तक कर दी है। मई में कपास आयात को पांच महीने यानी 31 अक्टूबर, 2026 तक के लिए सीमा शुल्क से छूट दी गयी थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, इस विस्तार से कपड़ा और परिधान क्षेत्र में उत्पादन लागत कम होने की उम्मीद है। इससे कपड़ा बनाने वाली कंपनियों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। साथ ही घरेलू किसानों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से बाजार में कपास की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी जिससे घरेलू कपड़ा उद्योग, विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

सत्ता, कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बीच फंसा टाटा समूह

सनत जैन

भारत के औद्योगिक जगत में इन दिनों एक बड़ा सवाल गूंज रहा है। क्या टाटा समूह, जो सौ साल से अधिक पुरानी कारोबारी परंपरा वाला समूह है, पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या देश के बड़े औद्योगिक घरानों के बीच प्रतिस्पर्धा अब बाजार तक सीमित नहीं रही। इसका असर सत्ता और सरकार की नीतियों तक पहुंच गया है? टाटा संस की लिस्टिंग का विवाद, रिलायंस समूह के अमेरीका के साथ बढ़ते कारोबारी रिश्ते एवं सरकार से नजदीकियां, भारत और दुनिया के देशों में अडानी समूह को लेकर उठते राजनीतिक सवाल को गंभीर बना रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी परिसर की यात्रा ने इस चर्चाओं को नया आयाम दिया है। अमेरिका, वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल के प्रसंस्करण में रिलायंस की क्षमता का इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है। दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी परिसरों में शामिल जामनगर की तकनीकी क्षमता रिलायंस को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में महत्वपूर्ण स्थान देती है। दूसरी ओर, एलन मस्क ने भारत में स्टारलिंक की शुरुआत में आ रही बाधाओं पर मुकेश अंबानी को व्यंग्यात्मक ढंग से देश का प्रधानमंत्री संबोधित किया। ये घटनाएं बताती हैं, भारतीय उद्योगपतियों का प्रभाव अब अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और तकनीकी प्रतिस्पर्धा की बहस का भी हिस्सा बन गया है। इसी बीच टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग का प्रश्न निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2026 में टाटा संस की नियामकीय पंजीकरण से बाहर निकलने की मांग अस्वीकार कर दी। इससे कंपनी के लिए नियामकीय नियमों के अनुरूप लिस्टिंग का रास्ता महत्वपूर्ण हो गया है। टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इन ट्रस्टों के माध्यम से शिक्षा,



स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के अनेक कार्य किए जाते हैं। जिनसे भारत की जनता को कई दशकों से लाभ मिल रहा है। यहां पर एक सवाल महत्वपूर्ण है। क्या लिस्टिंग का अर्थ टाटा समूह पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना है? ऐसा निष्कर्ष इसलिए निकाला जा रहा है, पिछले एक दशक में नियमों में परिवर्तन करके बड़ी-बड़ी कंपनियों को ठिकाने लगा दिया गया है। भारत सरकार का झुकाव अडानी समूह की ओर है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से पारदर्शिता, जवाबदेही और निवेशकों की निगरानी बढ़ सकती है? इससे अपने-आप मालिकाना नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं जाता है। यहां इसलिए चिंता हो रही कि टाटा समूह का 100 वर्ष से अधिक का इतिहास है। उसकी अपनी एक विश्वसनीयता है। सरकार का हस्तक्षेप औद्योगिक समूह और कंपनियों में बढ़ता जा रहा है। कई कंपनियों में भारी परिवर्तन इसके पहले हो चुके हैं। इसको लेकर टाटा समूह का चिंतित होना स्वाभाविक है। सरकार, सेबी एवं संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से सरकार का दबाव देखने को मिलता है। उससे नियामकीय बदलावों और प्रबंधन संबंधी विवादों का असर समूह की स्वतंत्रता, दीर्घकालीन निवेश और कारोबारी परिवारों के प्रबंधन पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। टाटा समूह ट्रस्ट की ओर से जो परोपकार करता आया है उस पर क्या अंतर आएगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टाटा समूह के घटनाक्रम पर सरकार और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है, टाटा समूह को कमजोर किया जा रहा है, ऐसे समय पर उद्योग जगत मौन क्यों है? ये गंभीर राजनीतिक आरोप हैं। इसका असर भारतीय राजनीति में बड़ी तेजी के साथ होना शुरू हो गया है। जो कारोबारी अभी डर और भय से चुपचाप बैठे थे, वह आगे चलकर मुखर हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवालों का उत्तर देना सरकार और नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी है। टाटा, रिलायंस और अडानी- तीनों भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण औद्योगिक कारोबारी समूह हैं। इनके बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा का आधार सरकारी संरक्षण नहीं, बल्कि निवेश, तकनीक, गुणवत्ता और नवाचार होना चाहिए। यदि किसी कंपनी को राजनीतिक निकटता से लाभ और किसी दूसरी को नियामकीय दबाव से नुकसान होता है, तो संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। भारत को ऐसे उद्योग चाहिए जो रोजगार दें, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ें और सामाजिक दायित्व भी निभाएं। टाटा समूह का भविष्य किसी राजनीतिक दल की जीत या हार का विषय नहीं होना चाहिए।



छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस

राज्योत्सव 2026

सशक्त नारी, युवा उड़ान



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

01 नवंबर 2026

शुभारंभ समारोह

राज्योत्सव मैदान
नवा रायपुर अटल नगर
(छत्तीसगढ़)

मुख्य अतिथि

डॉ. मनसुख मांडविया
माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार,
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, भारत सरकार

अध्यक्षता

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विशिष्ट अतिथि

डॉ. रमन सिंह
माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा

श्री तोखन साहू
माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री, भारत सरकार

श्री अरुण साव
माननीय उप मुख्यमंत्री,छत्तीसगढ़

श्री विजय शर्मा
माननीय उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

एवं

समस्त माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, निगम, मंडल, आयोग, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण
माननीय महापौर की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित है।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की

सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं...

पीएम आवास योजना
24.54 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को पक्की छत

कृषक कल्याणकारी योजनाओं से
₹1.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों को अंतरित

डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा **ट्राइबल हेरिटेज** व **ईको टूरिज्म** को बढ़ावा

सड़कों का विकास
₹40 हजार करोड़ से अधिक की लागत से राजमार्गों का विकास



विकास विश्वास विजन

संवर रहा छत्तीसगढ़

महतारी वंदन योजना
68 लाख महिलाओं को **₹20,708 करोड़** से अधिक की राशि अंतरित

इन्वेस्ट छत्तीसगढ़
₹8.60 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त

रेलवे का विस्तार
₹54,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन

जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन
बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक, बस्तर पण्डुम का निरंतर आयोजन

सेवा सेतु जनता के द्वार, डिजिटल सरकार
38 विभागों की **953 सेवाएं** एक ही प्लेटफॉर्म पर

हमसे जुड़ने के लिए **QR स्कैन करें**

सीएम हेल्पलाइन 1076
हर शिकायत की सुनवाई
हर समस्या का समाधान

RO No.49660/151

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.